वर्ष 12 • अंक 219 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 1 नवंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

# बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

सराफा बैंक शुरू करने का सुझाव

अजय त्यागी पृष्ठ 3

बैंकों के लिए परिसंपत्ति गुणवत्ता खुलासा नियम सख्त

डॉलर रु. 70.90 अपरिवर्तित | यूरो रु. 79.20 ▲ 40 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 38641 ▲ 324 रुपये | सेंसेक्स 40129.10 ▲ 77.20 | निफ्टी 11877.50 ▲ 33.40 | निफ्टी फ्यूचर्स 11914.80 ▲ 37.30 | ब्रेंट क्रूड 59.90 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

## एक नज़र

### बाजार में तेजी, नई ऊंचाई को छू आया सेंसेक्स

बेंचमार्क सूचकांक गुरुवार को कारोबारी सत्र में नई ऊंचाई को छू गया क्योंकि कर कटौती की उम्मीद ने अवधारणा में मजबूती बनाए रखी। हालांकि बाद में सूचकांक ने अपनी ज्यादातर तेजी गंवा दी। बेंचमार्क सेंसेक्स कारोबारी सत्र के दौरान 340 अंक तक चढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 40,392 अंक को छू गया। इससे पहले का सर्वोच्च स्तर 4 जून को देखने को मिला था जब सेंसेक्स 40,312 तक चढ़ गया था। कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 77.18 अंक चढ़कर 40,129.05 पर बंद हुआ। पृष्ठ 3

### पहली छमाही में राजकोषीय घाटा 93 प्रतिशत पर पहुंचा

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में बजट अनुमान के 92.6 प्रतिशत पर पहुंच गया है। कर राजस्व लक्ष्य के मुताबिक नहीं मिलने और व्यय में भी बहुत कमी नहीं करने की वजह से घाटा बढ़ा है। हालांकि यह पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही के 95.3 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा कम है। लेकिन वित्त वर्ष 2019 में राजकोषीय चूक हुई थी और 3.3 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत हो गया था। उस हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के लक्ष्य पर बरकरार रख सकती है। पृष्ठ 4

### जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील

जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई व्यवस्था का लक्ष्य विश्वास की मजबूत कड़ी बनाना है। हालांकि कश्मीर घाटी में पिछले 88 दिनों की तरह गुरुवार को भी बंद रहा। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को और लद्दाख का उप राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया है। पृष्ठ 14

### आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप से 4 नवंबर तक मांगा जवाब

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने इजरायली स्पाईवेयर (जासूसी सॉफ्टवेयर) के मुद्दे पर व्हाट्सऐप से जवाब मांगा है। व्हाट्सऐप से अपना जवाब 4 नवंबर तक देने को कहा गया है। व्हाट्सऐप ने कहा है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिये कुछ अज्ञात इकाइयां वैश्विक स्तर पर जासूसी कर रही हैं। भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने इस बारे में व्हाट्सऐप को पत्र लिखकर अपना जवाब देने को कहा है। व्हाट्सऐप ने कहा है कि वह एनएसओ समूह के खिलाफ मुकदमा करने जा रही है। यह इजरायल की निगरानी करने वाली कंपनी है। पृष्ठ 14

**व्यापार गोष्ठी**

**क्या हो प्रदूषण रोकने का स्थायी समाधान?**

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

**आज का सवाल**

**क्या बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में गिरावट नरमी का संकेत है**

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

**पिछले सवाल का नतीजा**

| | | |
|---|---|---|
| क्या जियो के रुख से दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ेगी उथल-पुथल? | हां | 64.71% |
| | नहीं | 35.29% |

# उद्योगों की हिली बुनियाद

## आठ में से सात उद्योगों का घटा उत्पादन, दूसरी छमाही की जीडीपी वृद्धि पर असर संभव

**शुभायन चक्रवर्ती**
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर

देश के प्रमुख आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन सितंबर में 5.2 फीसदी घट गया। इन आठ उद्योगों में से सात में गिरावट आई है। देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में इन क्षेत्रों का 40 फीसदी भारांश है। इस साल की पहली छमाही में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर महज 1.3 फीसदी रही जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसमें 5.5 फीसदी का इजाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर भी छह साल के निचले स्तर 5 फीसदी पर रही है।

बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में भी महज 0.1 फीसदी बढ़ा था। प्रारंभिक आंकड़ों में इसमें 0.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी लेकिन बाद में इसे संशोधित किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि उर्वरक को छोड़कर अन्य सात- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील, सीमेंट और बिजली क्षेत्र के उत्पादन में सितंबर में गिरावट आई है। कोयले के उत्पादन में तो 20.5 फीसदी की तेज गिरावट आई है।

**उत्पादन में गिरावट**

1 साल में उत्पादन (% बदलाव)

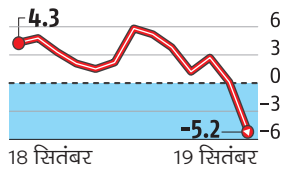


दूसरी तिमाही में क्षेत्रवार प्रदर्शन (% बदलाव)

| | |
|---|---|
| कोयला | -20.5 |
| कच्चा तेल | -5.4 |
| प्राकृतिक गैस | -4.9 |
| रिफाइनरी उत्पाद | -6.7 |
| उर्वरक | 5.4 |
| स्टील | -0.3 |
| सीमेंट | -2.1 |
| बिजली | -3.7 |
| कुल | -5.2 |

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बुनियादी क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट घरेलू उद्योगों में गहरी स्थिरता को दर्शाता है। इंडिया रेटिंग्स में प्रधान अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा, 'बुनियादी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में इस कदर गिरावट 2011-12 आधार श्रृंखला या 2004-05 आधार श्रृंखला में अब तक नहीं देखी गई है। यह अद्यौगिक नरमी की गंभीरता का स्पष्ट संकेत है।'

बुनियादी उद्योगों के कमतर प्रदर्शन से आईआईपी पर भी असर पड़ेगा। अगस्त में आईआईपी में भी 1.1 फीसदी की गिरावट आई थी, जो सात साल का निचला स्तर था। रिफाइनरी उत्पादन में उतार-चढ़ाव की वजह से बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर में कमी आई है क्योंकि इस सूचकांक में रिफाइनरी उत्पादों का भारांश करीब 30 फीसदी है। रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन सितंबर में 6.7 फीसदी घटा है। वित्त वर्ष 2020 में इस क्षेत्र में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि अगस्त में इसमें 2.6 फीसदी की वृद्धि देखी गई थी। कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट का रुख बना हुआ है। इसमें पिछले 12 महीने से लगातार गिरावट आ रही है। सितंबर में भी इसका उत्पादन 5.4 फीसदी घटा है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी लगातार छठे महीने गिरावट दर्ज की गई।

सितंबर में कोयले के उत्पादन में तेज गिरावट चिंताजनक है। इसके उत्पादन में 20 फीसदी की गिरावट आई है।

# वैश्विक निवेशक का येस बैंक में होगा निवेश!

**सुब्रत पांडा और श्रीपाद ऑटे**
मुंबई, 31 अक्टूबर

**येस** बैंक ने आज कहा कि ताजा इक्विटी शेयर के जरिये उसे एक वैश्विक निवेशक से 1.2 अरब डॉलर के निवेश की बाध्यकारी पेशकश मिली है। इस खबर का येस बैंक के शेयर पर अच्छा असर पड़ा और वह 24 फीसदी बढ़त के साथ 70.45 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 35 फीसदी तक चढ़ गया था। यह तीसरा मौका है जब येस बैंक के शेयर में एक दिन में इतनी बड़ी तेजी आई है। इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में शेयर 33 फीसदी और फरवरी के मध्य में 30.7 फीसदी चढ़ा था।

**येस बैंक के शेयर में उछाल**
कीमत रुपये में

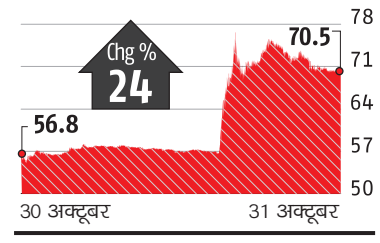


स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में ऋणदाता ने कहा, 'बैंक को एक विदेशी निवेशक से 1.2 अरब डॉलर के निवेश का बाध्यकारी ऑफर मिला है। यह निवेश ताजा इक्विटी के माध्यम से किया जाएगा, जो नियामक के साथ ही बैंक के निदेशक मंडल और शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा।'

पिछले महीने येस बैंक ने कहा था कि कई विदेशी निवेशकों के साथ ही घरेलू प्राइवेट इक्विटी एवं रणनीतिक निवेशकों ने पूंजी निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। यह भी चर्चा थी कि बैंक वैश्विक तकनीकी कंपनी के साथ रणनीतिक निवेशक के लिए बात कर रही है। हालांकि उक्त निवेशक का नाम उजागर नहीं किया गया था। येस बैंक ने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया था।

येस बैंक को पूंजी की सख्त जरूरत है क्योंकि फंसे कर्ज की वजह से बैंक की वृद्धि और टियर-1 पूंजी प्रभावित हो रही है। कुछ समय पहले बिज़नेस स्टैंडर्ड को दिए साक्षात्कार में येस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी रवनीत गिल ने कहा था, 'हमारी पहली प्राथमिकता पूंजी है। हम अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करना चाहते हैं। हम 1 से 1.2 अरब डॉलर पूंजी जुटाने की अपनी पूर्व की योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'

(शेष पृष्ठ 2 पर)

# जेवर हवाईअड्डे की होड़ में 4 कंपनियां

**अरिंदम मजूमदार**
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर

**जेवर** हवाईअड्डे के निर्माण और परिचालन के लिए देश की बुनियादी क्षेत्र की दो शीर्ष कंपनियों समेत चार कंपनियों ने बोली लगाई है। सूत्रों के मुताबिक अदाणी समूह, दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल), कनाडा की फेयरफैक्स फाइनैंशियल होल्डिंग्स और ज्यूरिख एयरपोर्ट ने इस परियोजना के लिए प्रस्ताव सौंपे हैं। इसमें करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है। डायल का परिचालन जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर करती है। तकनीकी बोली 6 नवंबर को और वित्तीय बोली 29 नवंबर को खोली जाएगी।

जेवर हवाईअड्डे की कार्यदायी संस्था यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने कहा, 'हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कुल चार बोलीदाताओं ने बोली लगाई है जो हमारे लिए उत्साहजनक है क्योंकि जेवर एक नया हवाईअड्डा है। बोली प्रति यात्री के आधार पर होगी और यह एक चरण में संपन्न होगी। इसी साल 29 नवंबर को निविदा को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।' उन्होंने बोली लगाने वाली कंपनियों के नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया। भाटिया ने कहा कि परियोजना का काम 2020 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है और पहले चरण का काम 2023 तक पूरा हो सकता है।

- अदाणी, जीएमआर, फेयरफैक्स और ज्यूरिख एयरपोर्ट ने लगाई बोली
- 6 नंबवर को तकनीकी बोली और 29 नवंबर को वित्तीय बोली खुलेगी
- जीएमआर को पहले इनकार का अधिकार

जेवर हवाईअड्डे की परियोजना काफी समय से लटकी है। 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा था। मायावती ने भी 2007 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें दिलचस्पी दिखाई लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली हवाईअड्डे की क्षमता अगले दशक में पूरी हो जाएगी। यही वजह है कि जेवर में हवाईअड्डे की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली हवाईअड्डे से वित्त वर्ष 2018-19 में 6.6 करोड़ लोगों ने सफर किया और यह एशिया का सातवां सबसे बड़ा हवाईअड्डा बन गया है। अगले तीन-चार साल में जब इसकी चौथी उड़ान पट्टी और चौथा टर्मिनल शुरू होगा तो यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

जीएमआर के स्वामित्व वाली डायल दिल्ली हवाईअड्डे का परिचालन करती है और जेवर हवाईअड्डे के लिए पहले इनकार का अधिकार उसी को है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

**टीवीएस और बजाज का पेटेंट विवाद सुलझा :** टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो का करीब एक दशक पुराना पेटेंट विवाद सुलझ गया है। दोनों ने स्पार्क प्लग से संबंधित पेटेंट विवाद को निपटाने के लिए एक सुलह समझौता किया है। दोनों ने 31 अक्टूबर को समझौते पर हस्ताक्षर किए। पृष्ठ 2

# 13 हजार की छंटनी करेगी कॉग्निजेंट

**देवाशिष महापात्र और गिरीश बाबू**
बेंगलूरु/चेन्नई, 31 अक्टूबर

**सूचना** प्रौद्योगिक सेवा प्रदाता कंपनी कॉग्निजेंट ने आज कहा कि वह लागत कम करने के लिए मध्य से वरिष्ठ स्तर के 7,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। साथ ही उसकी कंटेंट कारोबार को भी बंद करने की योजना है जिससे 6,000 अन्य कर्मचारियों के भी प्रभावित होने की आशंका है।

नैसडैक में सूचीबद्ध इस कंपनी के 30 सितंबर को समाप्त तीसरी तिमाही के परिणाम अनुमानों के मुताबिक रहे। कंपनी ने परिणामों के साथ ही लागत कम करने के उपायों की भी घोषणा की। कंपनी को टीसीएस और इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनियों से कड़ी चुनौती मिल रही है। भारत में इस कंपनी के 13 केंद्रों में करीब 200,000 कर्मचारी हैं। यह संख्या दुनियाभर में कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 70 फीसदी है।

हालांकि अमेरिकी कंपनी ने भारत में अपनी पुनर्गठन योजनाओं के बारे में नहीं बताया लेकिन इससे कंपनी के भारतीय कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई। आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों की स्वघोषित संस्था फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉईज ने कॉग्निजेंट के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

2019 की तीसरी तिमाही में कॉग्निजेंट का शुद्ध मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 4.1 फीसदी बढ़कर 49.7 करोड़ डॉलर रहा। पिछले साल उसने इस दौरान 47.7 करोड़ डॉलर का मुनाफा अर्जित किया था। क्रमिक आधार पर कंपनी का शुद्ध मुनाफा 2.4 फीसदी घटा है।

सितंबर तिमाही में कंपनी का राजस्व 4.25 अरब डॉलर रहा जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 4.2 फीसदी और पिछली तिमाही से 2.65 फीसदी अधिक है। स्थिर मुद्रा संदर्भ में कॉग्निजेंट का राजस्व पिछले साल की तुलना में 5.1 फीसदी बढ़ा। इस दौरान कंपनी का डिजिटल राजस्व 20 फीसदी के दायरे में बढ़ा और कंपनी के कुल राजस्व में इसकी हिस्सेदारी 35 फीसदी रही।

कॉग्निजेंट ने पूरे साल के लिए अपने राजस्व अनुमान के निचले स्तर को बढ़ाया है। कंपनी का कहना है कि स्थिर मुद्रा संदर्भ में वह 2019 में अपने राजस्व में 4.6 से 4.7 फीसदी तक बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। पहले यह अनुमान 3.9 से 4.9 फीसदी था।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

- तीसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर राजस्व वृद्धि
- प्रतिस्पर्द्धा के कारण मुनाफा प्रभावित
- पूरे साल का राजस्व अनुमान बढ़ाया
- कंटेंट कारोबार भी बंद करेगी कंपनी

## खबरों में रहे स्टॉक

### टाटा ग्लोबल बेवरिजेस

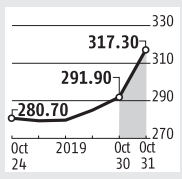


दूसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 28 फीसदी बढ़ा

₹ 291.90 पिछला बंद भाव
₹ 317.30 आज का बंद भाव
▲ 8.70 %

### क्वेस कॉर्प

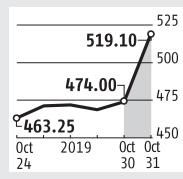


दूसरी तिमाही में एबिटा मार्जिन 73 आधार अंक बढ़ा

₹ 474.00 पिछला बंद भाव
₹ 519.10 आज का बंद भाव
▲ 9.51 %

### इन्फोसिस

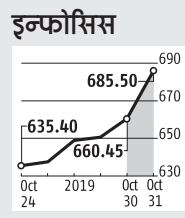


निफ्टी आईटी सूचकांक में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 660.45 पिछला बंद भाव
₹ 685.50 आज का बंद भाव
▲ 3.79 %

### इंटरनैशनल पेपर एपीपीएम

दूसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 79 फीसदी घटा

₹ 348.65 पिछला बंद भाव
₹ 315.90 आज का बंद भाव
▼ 9.39 %

### आरपीजी लाइफ साइंसेज

दूसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ चार गुना बढ़ा

₹ 212.25 पिछला बंद भाव
₹ 254.70 आज का बंद भाव
▲ 20.00 %

## संक्षेप में

### मुनाफे में लौटा सिंडिकेट बैंक

फंसे कर्ज के लिए प्रावधान घटने से सार्वजनिक क्षेत्र के सिंडिकेट बैंक ने सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 251.05 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक को 1,542.54 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भी बैंक को 980.46 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 6,153.10 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5,888.87 करोड़ रुपये रही थी। तिमाही के दौरान डूबे कर्ज और अन्य आकस्मिक खर्च के लिए बैंक का प्रावधान घटकर 683.94 करोड़ रुपये रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,217.26 करोड़ रुपये रहा था। *भाषा*

### धनलक्ष्मी बैंक की प्रबंध निदेशक ने दिया इस्तीफा

धनलक्ष्मी बैंक का शुद्ध लाभ 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में दोगुना होकर 22.07 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। फंसे कर्ज का अनुपात कम होना इसकी वजह रही। बैंक ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस बीच, बैंक की प्रबंध निदेशक और सीईओ टी लता ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। बैंक ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और इसकी सूचना आरबीआई को दे दी है। *भाषा*

# टीवीएस, बजाज में सुलह

## दोनों कंपनियों के बीच एक दशक से जारी पेटेंट विवाद सुलझा

**टीई नरसिम्हन**
चेन्नई, 31 अक्टूबर

टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो का करीब एक दशक पुराना पेटेंट विवाद सुलझ गया है। दोनों कंपनियों ने स्पार्क प्लग से संबंधित पेटेंट विवाद को निपटाने के लिए एक सुलह समझौता किया है। टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो ने 31 अक्टूबर को एक सुलह समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच पेटेंट संबंधी करीब एक दशक पुराना विवाद खत्म हो गया है।

बजाज ऑटो ने टीवीएस मोटर पर अपने पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया था और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी शुरू हो गई थी। टीवीएस मोटर ने बजाज ऑटो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। टीवीएस के एक बयान के अनुसार, दोनों कंपनियों के बीच कई मामले मद्रास उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (आईपीएबी), चेन्नई और श्रीलंका एवं मेक्सिको की अदालतों में लंबित थे।

### पेटेंट विवाद

- टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो ने 31 अक्टूबर को एक सुलह समझौते पर हस्ताक्षर किए
- बजाज ऑटो ने टीवीएस मोटर पर अपने पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया था और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी शुरू हो गई थी
- टीवीएस मोटर ने बजाज ऑटो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था
- विवाद तक शुरू हुआ जब टीवीए मोटर पर उसकी 125 सीसी बाइक फ्लेम में उस पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया

बजाज ऑटो का पेटेंट फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की विशेषताओं से संबंधित था। विवाद तक शुरू हुआ जब टीवीएस मोटर पर उसकी 125 सीसी बाइक फ्लेम में उस पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो दोनों ने आपसी सहमति से एक-दूसरे को उस पेटेंस से संबंधित सभी लंबित मामलों को वापस लेने और एक-दूसरे को सभी दायित्वों, दावों, मांगों एवं लंबित मामलों से संबंधित कार्रवाईयों से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

इस सुलह समझौते के तहत दोनों पक्षों में से किसी को भी किसी तरह के मुआवजे अथवा जुर्माने का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी ने कहा है कि इस सुलह समझौते से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गौरतलब है कि टीवीएस ने मद्रास उच्च न्यायालय में बजाज ऑटो लिमिटेड के खिलाफ इस आधार पर मुकदमा दायर किया था कि बजाज ने बिना किसी आधार के टीवीएस पर पेटेंट उल्लंघन का आरोप लगाया है।

# क्रैश टेस्ट में कमजोर निकलीं वैगन-आर, सैंट्रो और रेडिगो

**शैली सेठ मोहिले**
मुंबई, 31 अक्टूबर

**मारुति** सुजूकी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया और डैटसन के भारत में तैयार मॉडलों के नए वैरिएंट ब्रिटेन की कंपनी ग्लोबल एनसीएपी (न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम) द्वारा कराए गए क्रैश टेस्टिंग के ताजा राउंड में कमजोर साबित हुए हैं। कंपनी ने कहा है कि कार मॉडलों में सुरक्षा मानकों को सुधारने की पर्याप्त गुंजाइश है। भारत को दुनिया में सर्वाधिक सड़क हादसों वाले देशों में से एक के तौर पर कुख्याति हासिल है। देश में 2018 में 4,61,000 सड़क हादसे हुए।

इस क्रैश टेस्टिंग में जहां वैगन आर और अर्टिगा को पांच में से दो और तीन स्टार मिले, वहीं सैंट्रो और रेडि-गो को दो और एक स्टार से संतोष करना पड़ा। इस टेस्टिंग का छठा राउंड 'सेफर कार्स फॉर इंडिया केम्पेन' के तहत किया गया था, जिसे ब्लूमबर्ग फिलंथ्रोपीज और एफआईए फाउंडेशन-समर्थित जीएनसीएपी द्वारा शुरू किया गया। इस टेस्टिंग में प्रत्येक मॉडल के एंट्री-लेवल वर्सन को चुना गया। इसके परिणामस्वरूप, सिर्फ अर्टिगा ही मानक के तौर पर दो एयरबैग से फिट थी जबकि अन्य मॉडलों के तहत सिर्फ ड्राइवर एयरबैग की पेशकश की गई।

इन परिणामों से कारों में भारत सरकार के वाहन तकनीकी संबंधित नए नियमों के अनुकूल एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में बड़े अंतर का पता चला। ताजा परिणामों से मिश्रित सुरक्षा प्रदर्शन का पता चला। ग्लोबल एनसीएपी के मुख्य कार्याधिकारी एवं अध्यक्ष डेविड वार्ड ने कहा कि निराशाजनक बात यह है कि इस टेस्टिंग में कोई भी फाइव-स्टार प्रदर्शक साबित नहीं हुआ।

वार्ड ने कहा, 'सुजुकी मारुति अर्टिगा ने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों के लिए थ्री-स्टार हासिल किए हैं, लेकिन यह निश्चित है कि हमें बाजार में कारों की बिक्री के लिए कुल सुरक्षा स्तरों में सुधार लाना चाहिए।'

वैगनआर और सैंट्रो, दोनों ही सिर्फ ड्राइवर के सामने एयरबैग की पेशकश करती हैं। टेस्ट नतीजों के अनुसार, उनकी संरचना को 'अनस्टेबल' करार दिया गया। रेडिगो को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोजेक्शन के लिए महज एक स्टार मिला और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए दो स्टार मिले। इसकी निर्माण संरचना को भी 'अनस्टेबल' की रेटिंग मिली।

मारुति सुजूकी इंडिया और हुंडई मोटर इंडिया के अधिकारियों ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है।

### रीन्यू ने हासिल की 5,000 मेगावॉट की क्षमता

**रीन्यू** पावर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की उन वैश्विक कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है जिनकी स्थापित क्षमता 5,000 मेगावॉट से अधिक है। रीन्यू पावर इस सूची में शामिल होने वाली 11वीं कंपनी है। उसके पास 3,100 मेगावॉट की पवन ऊर्जा क्षमता और 1,900 मेगावॉट की सौर ऊर्जा क्षमता है। देश की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी ने राजस्थान के बीकानेर में अपने 250 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र को चालू किया है। रोबोटिक स्वच्छता तकनीक के साथ यह संयंत्र रीन्यू का दूसरा सबसे बड़ा सौर संयंत्र है। *बीएस*

# वोडाफोन ने अफवाहों का खंडन किया

**बीएस संवाददाता**
मुंबई, 31 अक्टूबर

**समायोजित** सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के रुख को लेकर बाजार में लगाए जा रहे तमाम कयासों के बीच कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम साझेदार ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप ने निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए अलग-अलग बयान जारी कर अफवाहों का खंडन किया है। कुछ खबरों में चिंता जताई गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वोडाफोन ग्रुप अपने इस भारतीय संयुक्त उद्यम से बाहर होने की संभावनाएं तलाशेगा। वोडाफोन ग्रुप ने एक बयान में कहा, 'वोडाफोन को भारतीय मीडिया में चल रहे इस निराधार एवं बेबुनियाद अफवाहों की जानकारी है कि हमने (भारतीय) बाजार से बाजार होने का निर्णय लिया है। लेकिन हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सही नहीं है।' वोडाफोन आइडिया ने कहा है, 'जहां तक वोडाफोन ग्रुप के भारतीय कारोबार से बाहर होने का सवाल है तो हम यह सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी को इस मामले में वोडाफोन ग्रुप से कोई जानकारी नहीं मिली है और इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।'

# पुरानी कंपनियां जल्द करें भुगतान: जियो

**बीएस संवाददाता**
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर

**रिलायंस** ने कहा है कि पुरानी दूरसंचार कंपनियों को उनके 1.33 लाख करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर करने के लिए कहा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बकाये के भुगतान के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। जियो ने कहा है कि पुरानी दूरसंचार कंपनियों के पास ऐसी क्षमता है जिससे वे अपने बकाये का भुगतान आसानी से कर सकती हैं।

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखे एक पत्र में जियो ने कहा है कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों की मौजूदगी के साथ जीवंत प्रतिस्पर्धा और नए ऑपरेटरों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध न होने के मद्देनजर पुराने दो प्रमुख ऑपरेटरों (वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल) द्वारा बकाये के भुगतान में विफलता से उद्योग परिदृश्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। जियो ने सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने सरकार को दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय संकट की एकपक्षीय जानकारी दी है।

जियो ने प्रसाद को लिखे पत्र में कहा है, 'हम यह बताना चाहते हैं कि तथाकथित प्रभावित सेवा प्रदाताओं के पास सरकारी बकाये का भुगतान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता मौजूद है। वे अपनी मौजूदा परिसंपत्तियों/निवेश को भुनाकर और अपनी कंपनी में ताजा इक्विटी जारी कर आसानी से भुगतान कर सकती हैं।' जियो ने कहा है कि वह सीओएआई की उस दलील से बिल्कुल असहमत है कि सरकार द्वारा तत्काल राहत न दिए जाने पर पूरा दूरसंचार क्षेत्र तहस-नहस हो जाएगा और इस क्षेत्र में एक अप्रत्याशित संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि तीन में से दो निजी ऑपरेटरों को गंभीर वित्तीय संकट से जूझना पड़ेगा। जियो ने कहा है कि उसके प्रवर्तकों ने दूरसंचार क्षेत्र में 1.75 लाख करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश किया है जबकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा किया गया इक्विटी निवेश पर्याप्त नहीं है। उसने कहा है कि पुराने ऑपरेटरों की विफलता का दोष सरकार पर नहीं मढ़ा जा सकता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता अपनी मौजूदा स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जियो ने कहा है कि उन्हें वित्तीय कुप्रबंधन और वाणिज्यिक विफलता से उबारने का दायित्व सरकार की नहीं होनी चाहिए।

# 13 हजार कर्मियों की छंटनी करेगी कॉग्निजेंट

**पृष्ठ 1 का शेष...**

**कंपनी** का कहना है कि पुनर्गठन उपायों के तहत 10,000 से 12,000 मध्य से वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को उनकी मौजूदा भूमिका से हटाया जाएगा और उनमें से 5,000 को दूसरे कामों का प्रशिक्षण देकर फिर से रखा जाएगा। इस तरह कंपनी छंटनी या काम खत्म करके 5,000 से 7,000 कर्मचारियों की कटौती करेगी। यह आंकड़ा कर्मचारियों की कुल संख्या का करीब दो फीसदी है। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ब्रायन हम्फ्रीज ने कहा, 'आज हम अपने परिचालन मॉडल को आसान बनाने और लागत में कटौती के कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। इससे हमें कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फंड मिलेगा। आने वाले दिनों में हम कंपनी की वृद्धि की पूरी संभावनाओं का रास्ता अपनाएंगे और कंपनी को फिर से उसके ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचाएंगे।'

कॉग्निजेंट ने साथ ही कंटेंट मॉडरेशन कारोबार से निकलने की घोषणा की है। कॉग्निजेंट फेसबुक जैसी कंपनियों को कंटेंट मॉडरेशन बिज़नेस मुहैया कराती है। इसके बंद होने से करीब 6,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। इससे कंपनी को सालाना 24 से 27 करोड़ डॉलर के राजस्व का नुकसान होगा।

# वैश्विक निवेशक करेंगे येस बैंक में निवेश

**पृष्ठ 1 का शेष...**

**गुरुवार** को बंद भाव के आधार पर पैसे जुटाने के लिए उसे करीब 47 फीसदी हिस्सेदारी बेचनी होगी। इनमें से नए निवेशक को करीब 32 फीसदी हिस्सा देना होगा। हालांकि बैंक ने यह भी कहा कि वह अन्य वैश्विक और घरेलू निवेशकों के साथ भी बात कर रहा है।

निजी बैंकों के स्वामित्व के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के मुताबिक कोई व्यक्ति बैंक की चुकता पूंजी की 10 फीसदी के बराबर हिस्सेदारी अपने पास रख सकता है। वित्तीय क्षेत्र की कंपनी (निगमित या विसाखित या सूचीबद्ध के अलावा) के लिए यह सीमा चुकता पूंजी की 15 फीसदी है।

लेकिन आरबीआई गैर प्रवर्तकों द्वारा पूंजी निवेश के जरिये ज्यादा

हिस्सेदारी लेने के लिए नियमों में ढील दे सकता है। निजी बैंकों में स्वामित्व के बारे में आरबीआई के परिपत्र में कहा गया है कि जिन बैंकों में नियामकीय मसले हैं और जहां केंद्रीय बैंक की नजर में जमाकर्ताओं के हित में बैंक के प्रबंधन में बदलाव जरूरी है, वहां किसी व्यक्ति को ज्यादा हिस्सेदारी के अधिग्रहण की अनुमति दी जा सकती है, भले ही संबंधित बैंक का निदेशक मंडल इसका समर्थन नहीं करता हो।

पिछले कुछ महीनों से येस बैंक ने बुरा दौर देखा है और अपने बहीखाते को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में है। जून तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा केवल 114 करोड़ रुपये रह गया था जबकि एक साल पहले यह 1,109 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में बैंक को 1,507 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

मार्च तिमाही में बैंक ने 3,661 करोड़ रुपये और जून तिमाही में 1,784 करोड़ रुपये का फंसे कर्ज के लिए प्रावधान किया था। बैंक का फंसा कर्ज लगातार बढ़ रहा है। संघर्ष कर रहे एनबीएफसी और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में उसका अच्छाखासा निवेश है।

# जेवर हवाई अड्डे की दौड़ में चार कंपनियां

**पृष्ठ 1 का शेष...**

**वर्ष** 2006 में दिल्ली हवाईअड्डे के निजीकरण के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जीएमआर इन्फ्रा के बीच हुए करार के मुताबिक दिल्ली हवाईअड्डे के 150 किमी के दायरे में बनने वाले किसी भी हवाईअड्डे के लिए पहले इनकार का अधिकार जीएमआर समूह को है।

नियमों के मुताबिक जीएमआर को बोली प्रक्रिया में मिली सबसे बड़ी बोली के बराबर बोली लगाने को कहा जाएगा। जीएमआर की बोली को तभी स्वीकार किया जाएगा जब यह सबसे अधिक बोली के बराबर या उससे दस फीसदी कम होगी। जीएमआर के लिए जेवर हवाईअड्डे का बोली जीतना जरूरी है, अन्यथा उसे परेशानी हो सकती है।

प्रतिद्वंद्वी कंपनी दिल्ली हवाईअड्डे से विमानन कंपनियों और यात्रियों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। दिल्ली हवाईअड्डा जीएमआर के पोर्टफोलियो में सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति है। लेकिन अदाणी समूह भी सक्रियता के साथ हवाईअड्डा कारोबार बढ़ाने में लगी है।

इसी साल कंपनी ने छह हवाईअड्डों के परिचालन के लिए प्रतिद्वंद्वियों से दोगुना बोली लगाई थी। प्रेम वत्स का फेयरफैक्स समूह भी बढ़चढ़कर भारत में बुनियादी परियोजनाओं में निवेश कर रही है।

# कारोबारी सत्र में नई ऊंचाई पर पहुंचा बीएसई सेंसेक्स

## सुधार की अटकल ने बाजार में तेजी बनाए रखी, बढ़त गंवाने से पहले तक सूचकांक में 340 अंकों की उछाल दर्ज हुई

**सुंदर सेतुरामन**
मुंबई, 31 अक्टूबर

बेंचमार्क सूचकांक गुरुवार को कारोबारी सत्र में नई ऊंचाई को छू गया क्योंकि कर कटौती की उम्मीद ने अवधारणा में मजबूती बनाए रखी। हालांकि सूचकांक ने अपनी ज्यादातर तेजी गंवा दी क्योंकि कुछ निवेशकों को इस संशय हुआ कि राजकोषीय अवरोध को देखते हुए क्या केंद्र सरकार कर कटौती का एक और दौर शुरू कर पाएगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से दरों में कटौती के बाद वैश्विक बाजार में उतारचढ़ाव दिखा, लेकिन फेडरल की तरफ से कटौती पर विराम के संकेत ने डेरिवेटिव अनुबंध की एक्सपायरी के बीच बिकवाली में इजाफा कर दिया।

बेंचमार्क सेंसेक्स कारोबारी सत्र के दौरान 340 अंक तक चढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 40,392 अंक को छू गया। इससे पहले का सर्वोच्च स्तर 4 जून को देखने को मिला था जब सेंसेक्स 40,312 अंक तक चढ़ गया था।

हालांकि इंडेक्स जून के सर्वोच्च स्तर से ऊपर बंद होने में नाकाम रहा। सेंसेक्स अंत में 77 अंक चढ़कर 40,129 पर बंद हुआ, जो पिछले सर्वोच्च स्तर से 140 अंक नीचे है। निफ्टी-50 इंडेक्स 37 अंकों की बढ़त के साथ 11,881 पर बंद हुआ।

सरकार की तरफ से लाभांश वितरण की समाप्ति और इक्विटी पर कर ढांचे को व्यावहारिक बनाने की खबरों के बीच पिछले पांच कारोबारी सत्रों में बाजार में उछाल देखने को मिली है। साथ ही उम्मीद से बेहतर आय की घोषणा और स्थिर वैश्विक बाजारों ने कुछ शेयरों को आगे बढ़ाया है।

इक्विनॉमिक्स रिसर्च ऐंड एडवाइजरी के संस्थापक जी चोकालिंगम ने कहा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से दरों में कटौती से विदेशी फंडों का प्रवाह बढ़ेगा। सेंसेक्स हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है, लेकिन व्यापक बाजार में कई शेयर अच्छे मूल्यांकन पर उपलब्ध हैं।

विकसित बाजारों में बॉन्ड प्रतिफल में नरमी के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने खरीदारी बढ़ाई है। गुरुवार को एफपीआई ने 1,870 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और इस तरह से एक दिन पहले 7,200 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड खरीदारी में और निवेश जोड़ दिया।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा, एफपीआई की तरफ से लगातार खरीदारी से माहौल सुधारने में मदद मिल रही है, लेकिन आर्थिक अवरोधों को देखते हुए निवेशकों को सतर्कता बरतनी चाहिए।

डाल्टन कैपिटल एडवाइजर्स के निदेशक यू आर भट्ट ने कहा, मौजूदा तेजी में 3-4 फीसदी से ज्यादा का इजाफा शायद ही हो पाएगा। सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बावजूद मांग या नए निवेश में ठीक-ठाक सुधार का संकेत नहीं दिखा है। आय की रफ्तार ने भी नहीं चौंकाया है, न ही व्यक्तिगत कर में कटौती का अनुमान सामने नजर आ रहा है। वैश्विक स्तर पर फेडरल रिजर्व ने दरों में कटौती की घोषणा की है, लेकिन अब इस पर विराम का संकेत दि[illegible] है। साथ ही अमेरिका-चीन व्या[illegible] वार्ता पर भी बहुत प्रगति नहीं [illegible]

सेंसेक्स में शामिल 18 [illegible] के शेयर चढ़े। येस बैं[illegible] सबसे ज्यादा 24 फी[illegible] लेनदार ने स्टॉक [illegible] सूचित किया कि [illegible] अरब डॉलर के [illegible] पेशकश ए[illegible] मिली है, [illegible] किए ज[illegible] 7.7 [illegible] औ[illegible]

### सेंसेक्स के शेयरों की बदल रही किस्मत

गुरुवार को बेंचमार्क सेंसेक्स कारोबारी सत्र के पिछले रिकॉर्ड उच्चस्तर 40,312 अंक के पार निकल गया, जो उसने 4 जून को दर्ज किया था। 30 ब्लूचिप शेयरों वाली कंपनियों का इंडेक्स अपनी बढ़त गंवाने से पहले कारोबारी सत्र में अब तक के नए सर्वोच्च स्तर 40,392 अंक को छू गया। अनिवार्य तौर पर सेंसेक्स अभी उसी स्तर पर है जो जून में था। हालांकि सेंसेक्स के कई शेयरों में नाटकीय बदलाव आया है। पिछले 100 दिनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेंसेक्स के शेयरों में एशियन पेंट्स (30 फीसदी), हिंदुस्तान यूनिलीवर (23 फीसदी) और बजाज फाइनैंस (16 फसदी) शामिल है। दूसरी ओर येस बैंक (52 फीसदी नीचे), टाटा स्टील (20 फीसदी नीचे) और इंडसइंड बैंक 18 फीसदी नीचे है। इंडेक्स के पॉइंट के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज (सेंसेक्स की बढ़त में 426 अंक का योगदान) और आईसीआईसीआई बैंक (289 अंक) ने सबसे ज्यादा योगदान किया है। वहीं आईटीसी (-178 अंक) और भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। 4 जून 2018 से सेंसेक्स के शेयरों ने सकारात्मक रिटर्न दिया है, लेकिन सिर्फ 6 शेयरों का रिटर्न दो अंकों में रहा है। नकारात्मक रिटर्न दर्ज करने वाले 14 शेयरों में से करीब एक दर्जन शेयरों में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। *समी मोडक*

| सबसे ज्यादा चढ़ने वाले | बदलाव (फीसदी) |
|---|---|
| एशियन पेंट्स | 29.66 |
| हिंदुस्तान यूनिलीवर | 23.46 |
| बजाज फाइनैंस | 16.20 |
| बजाज ऑटो | 13.48 |
| मारुति सुजूकी इंडिया | 11.64 |
| **सबसे ज्यादा गिरने वाले** | **बदलाव (फीसदी)** |
| येस बैंक | -51.73 |
| टाटा स्टील | -19.97 |
| इंडसइंड बैंक | -17.83 |
| ओएनजीसी | -17.12 |
| एसबीआई | -11.43 |

स्रोत : ब्लूमबर्ग। 4 जून के बाद से बदलाव

### प्रतिक्रिया

मुझे उम्[illegible] बजट [illegible] चम[illegible]

समझ रही [illegible] लिए जर[illegible]

रमेश [illegible]

## बाजार में तेजी से इक्विटी योजनाओं में सुधार

**बाजार के हालिया निचले स्तर के बाद चढ़ने वाले फंड**

| फंड | रिटर्न (फीसदी)* |
|---|---|
| क्वेंट ऐक्टिव फंड | 16.52 |
| क्वेंट टैक्स प्लान | 13.96 |
| डीएसपी टॉप 100 इक्विटी | 13.71 |
| निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर | 13.67 |
| डीएसपी फोकस फंड | 13.59 |
| मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी | 13.26 |
| **श्रेणी** | **रिटर्न (फीसदी)*** |
| लार्जकैप | 9.64 |
| ईएलएसएस | 9.24 |
| मल्टीकैप | 9.16 |
| लार्ज ऐंड मिडकैप | 8.84 |
| मिडकैप | 7.52 |
| वैल्यू फंड | 6.98 |
| स्मॉलकैप | 5.43 |

स्रोत : वैल्यू रिसर्च, रिटर्न 30 अक्टूबर 2019 तक का

बाजार में आई हालिया तेजी से इक्विटी योजनाओं का रिटर्न मजबूत हुआ है। विशाखित इक्विटी फंडों में लार्जकैप योजनाओं ने 19 सितंबर के बाद से 9.6 फीसदी रिटर्न दिया है, जब बेंचमार्क निफ्टी सात महीने के निचले स्तर तक फिसल गया था। तब से मिड और स्मॉलकैप योजनाओं ने क्रमशः 7.5 फीसदी व 5.4 फीसदी रिटर्न दिया है। हालिया तेजी की वजह 20 सितंबर को घोषित कंपनी कर में कटौती रही। तब से निफ्टी 10 फीसदी चढ़ा है। वैयक्तिक इक्विटी योजनाओं में क्वेंट ऐक्टिव फंड ने 16.5 फीसदी रिटर्न दिया है जबकि क्वेंट टैक्स प्लान (13.4 फीसदी), डीएसपी टॉप 100 (13.7 फीसदी), निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर (13.7 फीसदी), डीएसपी फोकस फंड (13.6 फीसदी) और मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी (13.3 फीसदी) रिटर्न दिया है। इसके अलावा आयकर में कटौती और इक्विटी निवेशकों को कर राहत मिलने की उम्मीद से बाजार में तेजी आई। त्योहारी सीजन में वाहनों की अच्छी बिक्री ने अवधारणा को और सकारात्मक बना दिया। गुरुवार को निफ्टी 11,900 के पार निकल गया जबकि सेंसेक्स ने नए और अब तक के सर्वोच्च स्तर 40,392.22 अंक को छू लिया। *जश कृपलानी*

## बैंकों के लिए परिसंपत्ति गुणवत्ता खुलासा [illegible]

**समी मोडक**
मुंबई, 31 अक्टूबर

**बाजार नियामक** सेबी ने गुरुवार को बैंकों के लिए परिसंपत्ति गुणवत्ता खुलासा नियमों को सख्त बना दिया। नियामक ने सभी सूचीबद्ध बैंकों को निर्देश दिया है कि वे प्रावधान आदि को लेकर खुलासा भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जोखिम का अंतिम आकलन रिपोर्ट (आरएआर) मिलने से एक दिन भीतर कर दें। इससे पहले बैंक सालाना वित्तीय विवरण के तहत यह खुलासा करते थे। साथ ही विगत में नियामकों ने कुछ बैंकों की तरफ से आरएआर से कुछ चुनिंदा खुलासा करने पर नाराजगी जताई थी। जोखिम का अंतिम आकलन रिपोर्ट (आरएआर) आरबीआई साल में एक बार देता है।

आपस में विचार-विमर्श के बाद सेबी व आरबीआई ने ऐसे खुलासे की सीमा तय की है। इनमें आरबीआई की तरफ से आकलित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान शामिल है।

सेबी ने कहा है कि यह खुलासा अकेले या दोनों मामलों में किया जाना चाहिए। यह कदम पारदर्शिता में सुधार और जोखिम के बेहतर आकलन में निवेशकों की मदद के लिए उठाया ग[illegible] है। सेबी ने एक परिपत्र में [illegible] प्रावधान आदि में अंतर को खुलासा तत्काल होना चा[illegible] ही यह सूचना कीम[illegible] संवेदनशील है, ऐसे मे[illegible] तुरंत होना चाहिए।

विशेषज्ञों ने दिशानिर्देशों [illegible] स्वविवेक [illegible] करते थे [illegible] कहा, [illegible] जोखि[illegible] अ[illegible]

## सऊदी अरब में आईओसी खोलेगी पेट्रोल पंप

**शाइन जैकब**
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर

**इंडियन ऑयल** कॉरपोरेशन पश्चिम एशिया में खुदरा बाजार में उतरने जा रही है और इसके तहत कंपनी का पहला पेट्रोल पंप अगले छह महीने में सऊदी अरब में खुल सकता है। इसके लिए कंपनी रियाद के अल जेरी समूह के साथ समान हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम बनाएगी। दोनों कंपनियों की योजना के मुताबिक, सऊदी अरब में शुरू में कम से कम 200 पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। आईओसी की शुरुआत अहम है क्योंकि सऊदी की नैशनल ऑयल कंपनी अरामको मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज संग गठजोड़ के जरिये भारतीय बाजार में प्रवेश पर विचार कर रही है।

हाल में प्रधानमंत्री के सऊदी अरब दौरे में आईओसी की पश्चिम एशिया इकाई और अल जेरी समूह के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वहां की कंपनी के पास थोक में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन व डिलिवरी की विशेषज्ञता है। आईओसी के निदेशक (विपणन) गुरमीत सिंह ने कहा, यह 50-50 हिस्सेदारी वाला संयुक्त उदद्यम होगा क्योंकि स्थानीय नियम के तहत खुदरा में प्रवेश के लिए सऊदी अरब का साझेदार होना जरूरी है। हम इस देश में ल्युब्रिकेंट्स बेच रहे हैं, जो अभी एक एजेंट के जरिए बेचा जा रहा है। सिंह ने कहा कि पहला पेट्रोल पंप अगले छह महीने में खुलेगा और कंपनियां स्थानीय मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं। हमने पेट्रोल पंप की संख्या पर फैसला नहीं लिया है।

### इंडियन ऑयल का लाभ 83 फीसदी घटा

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कर पूर्व लाभ सितंबर तिमाही में 83 फीसदी घटकर 814.48 करोड़ रुपये रह गया। इन्वेंट्री में ज्यादा नुकसान रिफाइनिंग मार्जिन में गिरावट का असर लाभ पर पड़ा। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी का कर पूर्व लाभ 4,805.74 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का शुद्ध लाभ 563.42 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 3.246.93 करोड़ रुपये रहा था। आईओसी के चेयरमैन संजीव सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तिमाही में लाभ में गिरावट की मुख्य वजह इन्वेंट्री में हुआ नुकसान है जबकि पिछले साल की समान अवधि में इन्वेंट्री में फायदा हुआ था। कंपनी का इन्वेंट्री नुकसान तिमाही में 1,807 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की समान अवधि में उसे इन्वेंट्री में उसे 2,895 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था। दूसरी ओर कंपनी का सकल रिफाइनिंग मार्जिन तिमाही के दौरान 1.28 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 6.79 डॉलर प्रति बैरल रहा था। *बीएस*

# वाणिज्य मंत्रियों की बैठक से सरकार को आस

**शुभायन चक्रवर्ती**
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर

बाजार तक पहुंच बनाने और शुल्क कम करने पर बातचीत का अभी कोई हल नहीं निकला है, ऐसे में सरकार अब क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसेप) देशों के वाणिज्य मंत्रियों की 2 नवंबर को होने वाली बैठक पर दांव लगा रही है, जिससे इन मसलों का समाधान हो सके।

अन्य मसलों के अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पर चीन से आयात की सीमा के प्रस्ताव पर बातचीत करने का खास दबाव होगा, जिसका चीन ने कड़ा विरोध किया है। मंत्रियों द्वारा तैयार किए गए एजेंडे पर आरसेप नेता 4 नवंबर को चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई संकेत नहीं दिया है कि भारत 4 नवंबर को होने वाले समझौते का हिस्सा होगा या नहीं। इस समझौते के लिए अंतिम तिथि 4 नवंबर रखी गई है, जब आरसेप देशों के प्रमुखों की बैठक होनी है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि भारत बातचीत पूरी होने की औपचारिक घोषणा का अब सैद्धांतिक रूप से समर्थन कर सकता है। बहरहाल यह नई दिल्ली पर निर्भर है कि वह आगे बातचीत जारी रखने के लिए अन्य देशों को किस तरह से मनाता है।

इस महीने की शुरुआत में तकनीकी चर्चा पूरी होने के बाद देशों ने यह कहा था कि असहमति के मसलों पर 22 अक्टूबर तक द्विपक्षीय बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। लेकिन उसके बाद से आगे कुछ भी नहीं हुआ है।

आरसेप बैठक के अलावा मोदी 16वें आसियान-भारत सम्मेलन और 14वें पूर्वी एशिया सम्मेलन व तीसरे क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसेप) से जुड़े अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

आरसेप भारत का सबसे महत्त्वाकांक्षी कारोबारी समझौता है, जिस पर इस समय बातचीत चल रही है। आसियान ब्लॉक के 10 देशों के साथ भारत के मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के आधार पर आरसेप में वे सभी देश शामिल होंगे,जिनका आसियान के साथ कारोबारी समझौता है। इनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान व दक्षिण कोरिया शामिल हैं।

सूत्रों ने कहा कि कारोबारी मसलों पर भारत की उम्मीदें पूरी होने पर भी अधिकारी जोर दे रहे हैं। इसमें अन्य देशों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में छूट दिए जाने का विरोध भी शामिल है। कारोबारी शब्द में 'रैचेट' नाम की इस अवधारणा के मुताबिक आरसेप के तहत कोई भी नीतिगत बदलाव एक तय अवधि तक सभी सदस्यों के लिए स्वत: बाध्यकारी होगी।

सभी साझेदार देशों को सबसे तरजीही देश (एमएफएन) का दर्जा देने को लेकर बात अटक गई थी। इसमें यह प्रावधान है कि भारत को आरसेप सदस्यों को बगैर किसी देरी द्विपक्षीय समझौते के तरह निवेश या सेवा संबंधी छूट देनी होगी।

भारत कुछ वस्तुओं पर अन्य आरसेप देशों को एमएफएन का लाभ संभवत: नहीं देगा। भारत ने शुल्क में कटौती की तिथि बढ़ाने की भी मांग की है क्योंकि इसने 3,500 से ज्यादा उत्पादों पर 2014 के बाद से सीमा शुल्क बढ़ाया है। बहरहाल इस मसले पर अब तक 29 दौर की बातचीत चली है।

बुधवार को गोयल ने कहा था कि प्रस्तावित कारोबारी वार्ता के आलोचकों को तब तक शांत रहना चाहिए, जब तक कि इसका ढांचा सार्वजनिक नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा था कि बातचीत को पटरी से उतारने के लिए लक्षित अभियान चलाया जा रहा है। गोयल ने यह भी कहा कि सरकार कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगी।

## बैंकॉक में आरसीईपी नेताओं की बैठक 4 नवंबर को

- 2 नवंबर को होगी आरसेप देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक, जहां भारत रखेगा अपना पक्ष
- भारत 4 नवंबर के परिणामों से जता सकता है सैद्धांतिक सहमति
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को 3 दिन की यात्रा पर बैंकॉक जाएंगे
- 4 नवंबर को होगी आरसीईपी देशों के प्रमुखों के साथ बैठक
- मोदी 16वें आसियान-भारत सम्मेलन और 14वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे

# एनबीएफसी की उच्च जोखिम वाले कर्जदारों में दिलचस्पी

**निधि राय**
मुंबई, 31 अक्टूबर

- **एनबीएफसी को ऐसे उच्च जोखिम वाले कर्जदार जिनका क्रेडिट स्कोर 700 से कम है, को कर्ज बांटने के लिए रुचि दिखाने में तकनीक से मदद मिल रही है। इसके लिए कर्जदारों के स्वभाव का आकलन प्रमुख कारण है**

**गैर-बैंकिंग** वित्तीय कंपनियां उच्च जोखिम वाले कर्जदारों को कर्ज बांटने में रुचि दिखा रही हैं। अपनी लोन बुक में विस्तार करने के लिए वे व्यक्तिगत और परिवारों को कर्ज दे रही हैं। इससे एनबीएफसी के साथ चूक करने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है जिसे कम करने के लिए वे एल्गोरिदम, ग्राहकों का सोशल मीडिया व्यवहार और जोखिम करने के विभिन्न उपायों को अपना रही हैं।

क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनियन सिबिल के एक अध्ययन से पता चलता है कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना ध्यान नियर प्राइम और सब प्राइम ग्राहकों को कर्ज बांटने की ओर बढ़ाया है। ऐसे ग्राहक जिनका क्रेडिट स्कोर 650 और 700 के बीच है उन्हें नियर प्राइम और 300 से 650 के बीच के क्रेडिट स्कोर वाले कर्जदारों को सब प्राइम श्रेणी में रखा जाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक 44.8 फीसदी नए कर्जदारों को जून 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान सब प्राइम और नियर प्राइम श्रेणी में रखा गया था जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में इन श्रेणियों में आने वाले कर्जदार 36.4 फीसदी थे।

ट्रांसयूनियन सिबिल के लिए शोध और परामर्श के उपाध्यक्ष अभय केलकर ने कहा, 'यह कर्जदाताओं के बीच अपने जोखिम अंकनों में ढील देने और उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को अधिक असुरक्षित कर्ज बांटने के प्रति बढ़ी हुई इच्छा की ओर इशारा करता है।'

# कारोबारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना होगा आसान

**बीएस संवाददाता**
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर

- **कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए देने होंगे अब आधे से भी कम दस्तावेज**
- **ऑनलाइन की डाउनलोड किया जा सकेगा ट्रेड लाइसेंस**
- **लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भौतिक सत्यापन से निजात**

**दिल्ली** के कारोबारियों के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना आसान होने जा रहा है। उत्तरी नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस के सरलीकरण के लिए बनी उपसमिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अब कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए आधे से भी कम दस्तावेज देने होंगे। लाइसेंस शुल्क भी ऑनलाइन भरा जाएगा और लाइसेंस को मंजूरी मिलने के बाद इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकता है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि आज स्थायी समिति की बैठक में ट्रेड लाइसेंस के सरलीकरण के लिए बनी उपसमिति की सिफारिशों को मंजूरी मिल गई। इन सिफारिशों के मुताबिक कारोबारियों को अब 11 की जगह 4 ही दस्तावेज देने होंगे। ये दस्तावेज कारोबारी प्रतिष्ठान के मालिकाना या किरायेदारी का कानूनी प्रमाण, खुद का पहचान पत्र, जीईओ लोकेशन के साथ प्रतिष्ठान के फोटो, स्वघोषणापत्र हैं। कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए पहले लिये जाने वाले बिल्डिंग प्लान, फर्म का संविधान, मैन्यूअली संचालित मशीनों की जानकारी, कन्वर्जन शुल्क भुगतान की रसीद, प्रदूषित प्रवृत्ति के कारोबार के संबंध में डीपीपीसी से अनुमति आदि दस्तावेजों से निजात देकर इस लाइसेंस का सरलीकरण किया गया है। लाइसेंस के आवेदन के साथ शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा होगा।

# श्रमिक संघ आंदोलन के नेता गुरुदास दासगुप्ता का निधन

**देश** में श्रमिक संघ आंदोलन के प्रमुख नेता एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद गुरुदास दासगुप्ता का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार सुबह कोलकाता में निधन हो गया। वह 83 साल के थे। भाकपा नेता के परिवार में पत्नी और एक पुत्री है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाकपा के वरिष्ठ नेता के निधन पर शोक जताया और कहा कि वह संसद की एक सशक्त आवाज थे। दासगुप्ता 1985 से अब तक पांच बार सांसद रहे। इस दौरान वह पश्चिम बंगाल से तीन बार राज्यसभा और दो बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनका जन्म तीन नवंबर 1936 को बारिशाल जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। 1947 में देश के बंटवारे के बाद वह अपने माता-पिता और भाई-बहन के साथ पश्चिम बंगाल आ गए। दासगुप्ता एक ऐसे नेता थे जो संसद के भीतर एवं बाहर श्रमिक वर्ग और आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाने से पीछे नहीं रहते थे। *भाषा*

# राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 93 प्रतिशत

**इंदिवजल धस्माना**
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर

**केंद्र** सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में बजट अनुमान के 92.6 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि कर राजस्व लक्ष्य के मुताबिक नहीं आया और व्यय में भी बहुत कमी नहीं की गई है।

यह आंकड़े गंभीर नजर आते हैं, लेकिन यह पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के 95.3 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा कम है। लेकिन वित्त वर्ष 19 में राजकोषीय चूक हुई थी और 3.3 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत हो गया था। उस हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के लक्ष्य पर बरकरार रख सकती है। हालांकि अक्टूबर के बाद कर राजस्व प्रभावित हो सकता है क्योंकि कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती की घोषणा की गई है।

इस अवधि के दौरान राजस्व घाटा बढ़कर बजट अनुमान के करीब 100 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जो व्यय और मौजूदा राजस्व जरूरतों के अंतर को दिखाता है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 108 प्रतिशत था। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि राजकोषीय घाटे से कहीं बहुत ज्यादा अहम राजस्व घाटा है क्योंकि सरकार को खपत के लिए उधारी लेनी होगी।

अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान कुल कर प्राप्तियां 6.07 लाख करोड़ रुपये रही हैं, जो बजट अनुमान का 36.8 प्रतिशत है। यह इसके पहले के वित्त वर्ष की पहली छमाही के 39.4 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा कम है।

इक्रा में प्रमुख अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'चिंता की बात है कि केंद्र का सकल कर राजस्व अगस्त और सितंबर 2019 में सालाना आधार पर गिरा है, जिसकी वजह से वित्त वर्ष 20 की पहली छमाही में 1.5 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई है।'

उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व दोनों मद से आने वाले कर राजस्व में उल्लेखनीय कमी आएगी, क्योंकि हाल के महीनों में प्रदर्शन सुस्त रहा है।

इसके अलावा सितंबर तक राजस्व के आंकड़ों में तेजी बनी रही क्योंकि रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं, जो अगली छमाही में नहीं रहेगा। रिजर्व बैंक के हस्तांतरण से केंद्र का पहली छमाही में कुल गैर कर राजस्व 2.09 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह 2019-20 के बजट अनुमान की तुलना में 66.7 प्रतिशत रहा, जो अप्रैल सितंबर 2018-19 के 44.5 प्रतिशत की तुलना में बहुत ज्यादा है।

इंडिया रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा, 'अगर रिजर्व बैंक से एकमुश्त अप्रत्याशित लाभ नहीं होता तो राजकोषीय घाटे की हालत बहुत खराब नजर आती।'

गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियों, जिसमें विनिवेश शामिल है, की रफ्तार सुस्त है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल सितंबर के दौरान यह 20,598 करोड़ रुपये रहा है, जो बजट अनुमान का 17.2 प्रतिशत है, जो एक साल पहले 19.2 प्रतिशत था। सरकार बड़े विनिवेश जैसे बीपीसीएल और एयर इंडिया पर नजर बनाए हुए है, जिससे 1.05 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल किया जा सके।

वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से सरकार ने व्यय में भी ज्यादा कटौती नहीं की है। राजस्व व्यय और पूंजीगत वव्यय दोनों ही पहले छह महीने में प्रतिशत के हिसाब से पिछले साल की समान अवधि के बराबर रहा है।

नायर ने कहा कि वित्त वर्ष 20 में राजकोषीय घाटे में तेज बढ़ोतरी रोकने के लिए व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है।

## पहली छमाही का हाल

- कर आया कम, कॉर्पोरेट कर में कटौती से आने वाले महीनों में कर राजस्व और कम होने का अनुमान
- पहली छमाही में रिजर्व बैंक द्वारा धन दिए जाने से आया राजस्व, दूसरी छमाही में इसका सहारा नहीं
- धाटा होने की बड़ी वजह मंदी के कारण खर्च न घटाना भी

# मुंबई-दिल्ली के रियल्टी बाजार से दूर प्रॉपर्टी फंड

**राघवेंद्र कामत**
मुंबई, 31 अक्टूबर

## सावधानी भरे कदम

- मोतीलाल ओसवाल मुंबई और एनसीआर में हल्का
- एनसीआर में निवेश के मामले में सुस्त ब्रुकफील्ड
- मुंबई के आवासीय क्षेत्र में ब्रुकफील्ड का निवेश नहीं
- ऐक्सिस म्युचुअल फंड का रियल्टी फंड मुंबई, एनसीआर और बड़े बाजारों से बच रही है
- एएसके प्रॉपर्टी फंड ने मुंबई में पिछले 4 साल से कुछ नहीं किया

**रियल** एस्टेट पर केंद्रित निजी इक्विटी फंडों ने मुंबई और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निवेश की रफ्तार सुस्त कर दी है। देश के इन दो बड़े बाजारों में प्रॉपर्टी डेवलपरों के नकदी के संकट और बिक्री में लंबे समय से चल रही सुस्ती के कारण फंडों का निवेश कम हुआ है।

मोतीलाल ओसवाल रियल एस्टेट (मोर) के मुख्य कार्यकारी शरद मित्तल ने कहा कि एनबीएफसी की ओर से कर्ज के संकट के बाद डेवलपर नकदी की कमी से जूझ रहे हैं और बेहतर डेवलपर साझेदार की कमी है, जिसकी वजह से फंड का यहां 'हल्का' रुख है। मित्तल ने कहा, 'हम संभावनाओं के दोहन के लिए डेवलपर साझेदारों पर निर्भर हैं लेकिन इस समय मुंबई में कोई भी काम का डेवलपर नहीं है। नोएडा में भी यही हा है और गुड़गांव में कुछ ही डेवलपर हैं।' मोतीलाल ओसवाल अपने चौथे रियल एस्टेट फंड के लि 1,200 करोड़ रुपये जुटा रही है।

प्रॉप इक्विटी रिसर्च के मुताबिक भारत के प्रमुख 9 शहरों में बड़े पैमाने पर डेवलपर मौजूद हैं। 2011-12 में मौजूद डेवलपरों में से 50 प्रतिशत से ज्यादा 2017-18 तक बाजार छोड़ चुके हैं। गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई में 2011 से करीब 70 प्रतिशत डेवलपरों का केंद्रण रहा है। कोलकाता और बेंगलूरु के बाजार में भी डेवलपरों की संख्या में 65 प्रतिशत से ज्यादा कमी आई है।

सूत्रों के मुताबिक कनाडा की ब्रुकफील्ड एनसीआर में कर्ज में निवेश को लेकर सुस्त रुख अपना रही है और उसने मुंबई के आवासीय क्षेत्र में हाल फिलहाल कोई निवेश नहीं किया है। सूत्रों ने कहा, 'हालांकि मुंबई में निवेश को लेकर उनका रुख सकारात्मक है, लेकिन वह किसी को ऐसा नहीं पा रहे हैं।' ब्रुकफील्ड ने पिछले दो साल में रियल एस्टेट डेवलपरों को 50 करोड़ डॉलर दिए हैं और वह अपने खाते को दोगुना करना चाहती है।

ब्रुकफील्ड ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है।

ऐक्सिस म्युचुअल फंज का रियल एस्टेट फंड भी यही रणनीति अपना रहा है। ऐक्सिस म्युचुल फंड के रियल एस्टेट में मैनेजिंग पार्टनर बालाजी राव ने कहा, 'हम मुंबई और एनसीआर से बच रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप बिक्री कर रहे हैं, उत्पाद वहनीय होने चाहिए। एनसीआर में बहुत ज्यादा दबाव है।' राव ने कहा कि वह पुणे, चेन्नई, बेंगलूरु और अहमदाबाद जैसे बाजारों को प्राथकिमता दे रहे हैं।

प्रॉपटाइगर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2019 तक मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन (एमएमआर) में 2.93 लाख बिना बिके फ्लैट हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है।

प्रॉपर्टी डेवलपरों को कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से हाल के नकदी संकट से उनकी पुनर्वित्तपोषण योजना प्रभावित हुई है, जो उनके वित्तपोषण के मुख्य स्रोत होते हैं। जीएसटी और रेरा जैसे कानूनों की वजह से बिक्री घटने के बाद उनकी जिंदगी कठिन हुई है।

नाइट फ्रैंक के चेयरमैन शिशिर बैजल ने कहा कि कुछ फंड हाउसों ने मझोले आवासीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है और वे छोटे बाजारों की ओर जा रहे हैं। एएसके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के मुख्य कार्यकारी अमित भगत का कहनाहै कि उन्होंने पिछले 4 साल से मुंबई क्षेत्र में कोई निवेश नहीं किया है क्योंकि उन्हें मध्य आय वर्ग के आवासों में कोई बेहतर मौका नहीं नजर आया। हालांकि उन्होंने हाल में एनसीआर में निवेश किया है। बहरहाल भगत ने कहा कि मुंबई में निवेश को लेकर उनके विकल्प खुले हुए हैं।

# सेबी में बदलेंगे तमाम शीर्ष चेहरे

**सचिन मामबटा**
मुंबई, 31 अक्टूबर

## शीर्ष पर बदलाव

- विभिन्न प्रमुख अधिकारियों का कार्यकाल अगली दो तिमाहियों में हो जाएगा पूरा
- दो नए कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई है शुरू
- साक्षात्कार का दौर है जारी
- अप्रैल में एक पूर्ण कालिक सदस्य का कार्यकाल भी हो जाएगा पूरा
- चेयरमैन का कार्यकाल मार्च तक

**भारतीय** प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अगले वित्त वर्ष से बहुत बदल हुआ नजर आ सकता है। अगले वित्त वर्ष के आरंभ होने तक इस संस्था के शीर्ष पर काबिज कई अधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। वहीं कुछ अधिकारी इससे पहले ही जा चुके होंगे।

नियामक पहले से ही कुछ प्रमुख पदों को भरने पर विचार कर रहा है। एक सूत्र के मुताबिक कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार चल रहे हैं। नियामक ने जुलाई में आवेदन मंगाए थे।

सेबी एक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति कानूनी विभाग में और दूसरे की सामान्य श्रेणी के तहत करने जा रहा है। दोनों पदो पर नियुक्ति तीन साल के लिए की जाएगी। आवेदन आमंत्रित करने के लिए 25 जुलाई को जारी किए गए नोटिस के मुताबिक इनके लिए वेतन पैकेज करीब 70 लाख रुपये सालाना है। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त पदों के लिए सेबी के अंदर कार्यरत उम्मीदवारों (सेबी में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत और मांगी गई सभी योग्यता को पूरा करने वाले उम्मीदवार) पर भी विचार किया जाएगा। इसके लिए पूरी कठोरता से उपयुक्तता और योग्यता का पालन किया जाएगा।

मामले से अवगत एक व्यक्ति के मुताबिक उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक नहीं है लेकिन शीघ्र ही इसका निर्णय किया जाना चाहिए। इस व्यक्ति ने कहा कहा कि उनके पास विकल्प बहुत सीमित है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी पहचान जाहिर करने से मना कर दिया।

स्टॉक मार्केट नियामक के तौर पर काम करने वाली इस संस्था की पिछली रिपोर्ट में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे सात कार्यकारी निदेशकों का उल्लेख था। इसमें शामिल नामों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और कस्टोडियन जैसी प्रमुख जिम्मेदारियों का वहन कर रहे पी के नागपाल, एकीकृत निगरानी विभाग सहित विभिन्न विभागों के इनचार्ज रहे एस रविंद्रन, सामूहिक निवेश योजनाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे एस वी मुरली धर राव, ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंस ऐंड एजुकेशन ऐंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट के नागेंद्र पारेख, कॉर्पोरेट वित्त की जिम्मेदारी देखने वाले अमरजीत सिंह, बाजार नियमन विभाग के सुजीत प्रसाद, जांच विभाग के आनंद राजेश्वर बैवर शामिल हैं।

कानूनी विभाग में एक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति पर करीब से नजर रहेगी। हालिया प्रमुख गतिविधियों में नियामक ने सत्यम घोटाला से जुड़े अंकेक्षकों प्राइस वाटरहाउस (पीडब्ल्यू) पर कार्रवाई करने के उसके निर्णय के खिलाफ फैसला आने के बाद उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। उसने खातों में धोखाधड़ी पकड़े जाने की स्थिति में अंकेक्षकों के ऊपर कार्यक्षेत्र पर प्रश्न खड़े किए थे। उसने कहा, 'प्रतिभूति अपील पंचाट में नियामक के खिलाफ आने वाले ज्यादातर मामलों में फैसला सेबी के पक्ष में हुआ है। नियामक के पक्ष में 138 अपीलों में फैसला आया जबकि केवल 25 अपीलों में फैसला नियामक के खिलाफ रहा।' फिलहाल 379 अपील लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी 156 मामले लंबित हैं जबकि पिछले वर्ष लंबित मामलों की संख्या 165 थी।

नियामक को भेजे गए ईमेल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

## बीएस सूडोकू 3575 | परिणाम संख्या 3574

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | 8 | | 9 | |
| | 6 | | 7 | | 3 | | | 4 |
| | | 7 | 9 | | | | 8 | |
| | | 1 | | | 2 | | | |
| | | 8 | | | | 4 | | |
| | | | 1 | | | 8 | | |
| | 8 | | | | 7 | 2 | | |
| 4 | | | 3 | | 1 | | 7 | |
| | 5 | | 8 | | | | 6 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 |
| 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 |
| 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 |

**कैसे खेलें?**
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

**बहुत आसान**
★☆☆☆☆

## क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

**कानपुर**
गेहूं लूज 2070/2080, जौ 1825/1850, चावल मसूरी 2325/2350, चावल मोटा 2225/2250,सरसों 4050/4100, तिल सफेद 9600/9700, सोया (टीन) 1325/1350, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1450/1525,

**लखनऊ**
गेहूं दड़ा 2050/2060, गेहूं शरबती 2750/2900, चावल शरबती सेला 3500/3600, स्टीम 3900/4000, लालमती 3000/3100, चावल (सोना) 2700/2750,

**चंदौसी**
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1390, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1495, फ्लैक 1425, डीएमओ 975, टरपीन लैस बोल्ड 1515

**मुजफ्फरनगर**
गुड़ (40 किलो): लड्डू नया 1050/1100, खुरपा 950/1000,चाकू 950/1100, रसकट 850/860, शक्कर 1180/1200, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3470, सिहोरा 3440, बुंदकी 3360, बुढ़ाना 3375,

**हापुड़**
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3700/3750, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1000/1040, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4150, खल: सरसों 2250/2350,

**जयपुर**
अनाज: चावल डीबी 5600/5800, गेहूं (मिल) 2120/2180, मक्की 2175/2180, बाजरा 1740/1750, जौ 1750/1800, ग्वार लूज 3800/3825, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4420/4425,

**श्रीगंगानगर**
गेहूं (देरी) 2000/2050, ग्वार 3800/3825, जौ 2080/2090,

**जोधपुर**
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7700/7750, बाजरा (गुजरात) 1790/1800, बाजरा (जयपुर) 1775/1780, चना 4200/4300,

**खन्ना**
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)130, राइसब्रान (अखाद्य) 127, खल सरसों 2020, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1470, लाल 1450, कंटीन्यूअस 1450,

**लुधियाना**
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7300/8100, अरहर दाल 7600/8100, उड़द साबुत 6700/7600, उड़द धोया 7500/8700, छिलका 7500/8200, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

**अमृतसर**
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम नया 6300/6400, सेला 5400/5500, शरबती साधारण सेला 3400/3500, शरबती स्टीम नया 3800/3900, चावल 1509 सेला नया 4700/4800,

**बठिंडा**
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3900/3925, हरियाणा 3910/3950, राजस्थान 3880/3930, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2800/2900, सरसों खल 2175/2180, गेहूं चोकर (28 किलो) 580

**फाजिल्का**
गेहूं 2145/2150, सरसों 4000/4100 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3900/3925,कपास देशी 4800/4825, कपास नरमा (क्विं.) 5000/5200, बिनौला (टैक्सपेड): खल 3500/3600,

**जालंधर**
गेहूं दड़ा 2130/2140, चावल परमल कच्चा 2375/2450, से ला 2340/2400, मक्की यूपी 2090/2100, बिहार 2130/2140, दाल उड़द छिलका 8200/9800, चना देशी 5300/5350, दाल चना 5500/5600, काबली चना 5100/6100, राजमां चित्रा पुणे 7300/8800,चीन 7500/8200, शर्मिली 5500/6100,

**करनाल**
गेहूं दड़ा 2080/2090, बासमती चावल 7000/7200, धान 1121 नं. 2800/2950, पूसा 1509 धान 2500/2675, शरबती धान 1900/1925, सेला नया (1509 नं.) चावल 4700/4800,चना दाल 5500/5600

**हिसार**
ग्वार 3850/3875, सरसों 3900/3950, गेहूं 2090/2100, नरमा कपास 5000/5100

**जींद**
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 1950/2000, आटा (प्रति 44 किलो) 1075/1100, मैदा 1150/2000, देशी घी (एक ली/जार) 320/450, रिफाइंड (टीन) 1300/1320,

**भिवानी**
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3900/3950, खल बिनौला मोटी 3000/3050, बिनौला 3000/3300, सरसों तेल 8300/8350, गेहूं 2100/2150, ग्वार 3850/3900, बाजरा 1800/2000 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 219

# दूरसंचार संकट

**दूरसंचार** क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल है। इस दौरान सरकार के सामने भी कुछ गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जब से दूरसंचार विभाग की समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा पर सहमति जताई है और दूरसंचार कंपनियों को तीन महीने के भीतर 1.33 लाख करोड़ रुपये का बकाया ब्याज सहित चुकाने को कहा है तब से नए किस्म का संकट आ खड़ा हुआ है। पहले से काम कर रही कंपनियों पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है। इन कंपनियों ने कहा है कि वे यह राशि चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने यह राशि माफ करने की मांग भी की है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) का कहना है कि इस निर्णय से बाजार में एकाधिकार आएगा और सरकार के डिजिटलीकरण के कार्यक्रम को भी झटका लगेगा। परंतु बाजार में आने वाली सबसे नई कंपनी रिलायंस जियो, जिसने बाजार में उथलपुथल मचा दी थी, ने सीओएआई के 'डराने और ब्लैकमेल करने वाले रुख' पर आपत्ति जताई है। इस बीच इस क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों की कीमत पर असर पड़ा है। इन कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग कम की गई है और इनमें से कम से कम एक कंपनी के बारे में खबर है कि वह कर्जदाताओं के साथ पुनर्भुगतान की बेहतर शर्तों को लेकर चर्चा कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने मौजूदा कंपनियों को जबरदस्त झटका पहुंचाया है और यह केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व के एक नियमित स्रोत को भी समाप्त कर सकती है।

सरकार ने इस क्षेत्र पर से वित्तीय तनाव समाप्त करने संबंधी सुझाव देने के लिए सचिवों की समिति का गठन करके सही किया है। समिति और इससे आगे सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि वे इस मसले पर कहीं अधिक व्यापक दृष्टि डालें और कुछ बुनियादी नीतिगत सवालों को हल करें। पहली बात, मौजूदा कंपनियों ने इतना ऋण क्यों एकत्रित किया? यह राशि केवल कारोबारी प्रबंधन की वजह से नहीं हुई है बल्कि इस क्षेत्र में बीते वर्षों के दौरान हुए नीतिगत और नियामकीय बदलाव ने भी असर डाला है। इसकी वजह से क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण भी हुआ क्योंकि कई दूरसंचार कंपनियां कारोबार से बाहर हो गईं या बंद हो गईं। अतीत के निर्णयों पर समग्र दृष्टि डालकर ही सरकार नीतिगत सुधार कर सकती है। इससे इस क्षेत्र के तनाव में स्थायी कमी करने में मदद मिलेगी। दूसरा, क्या आगे और सुदृढ़ीकरण से इस क्षेत्र और ग्राहकों को मदद मिलेगी? विश्लेषकों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जो बकाया उत्पन्न हुआ है उसके बाद बाजार में केवल निजी क्षेत्र के दो कारोबारी ही रह जाएंगे। इसका असर सेवाओं की गुणवत्ता और निवेश पर पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह मामला गैर किफायती कंपनियों को बचाने का नहीं है। एक और सेवा प्रदाता के बाजार से बाहर होने को अकेले परिचालन मानकों से नहीं समझाया जा सकता।

तीसरा, सरकार को यह निर्णय लेना है कि वह इस क्षेत्र से क्या अपेक्षा करती है? एक ओर, निजी सेवा प्रदाताओं को पीछे धकेल दिया गया है और वहीं दूसरी ओर वह गैर किफायती सरकारी कंपनियों को रियायतों के साथ पुनर्जीवन प्रदान कर रही है। इससे परिसंपत्तियों का गलत आवंटन होगा और बाजार में विसंगति आएगी। इतना ही नहीं यह भी देखना उचित होगा कि सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए दूरसंचार कंपनियों को निचोड़ना जारी रखना चाहिए या उसे उनकी निवेश करने की क्षमता पर भी विचार करना चाहिए। उसे संतुलन कायम करने पर विचार करना चाहिए। इनमें से कुछ सवालों का साफ जवाब सरकार को सही फैसला लेने में मदद करेगा। देश का दूरसंचार क्षेत्र बहुत अहम मोड़ पर है और सरकार का इस क्षेत्र के साथ व्यवहार न केवल इसे प्रभावित करेगा बल्कि निवेश के माहौल पर भी असर डालेगा।

अजय मोहंती

# पीएमसी संकट के लिए सरकार क्यों जिम्मेदार?

सरकार ने ग्राहकों को कभी नहीं बताया कि सामान्य वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में इन बैंकों में किस तरह के जोखिम ज्यादा हैं। इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं **देवाशिष बसु**

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा धोखाधड़ी के शिकार पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में सामान्य कामकाज को स्थगित किए एक महीने का वक्त बीत चुका है। आरबीआई ने एक प्रशासक की नियुक्ति की है जिसके पास तमाम अन्य कौशल चाहे जितने हों लेकिन उसने कभी कोई बैंक नहीं चलाया है, भारी धोखाधड़ी के शिकार किसी बैंक की बात तो छोड़ ही दें। तीन अन्य बैंकरों की सहायता के साथ प्रशासक का काम है समस्या का हल निकालना लेकिन समुचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए। अगर अतीत के सबक से कुछ सीखें तो इस पूरी प्रक्रिया में पीएमसी बैंक शायद किसी काम का नहीं रहेगा। यह एक जॉम्बी बैंक बनकर रह जाएगा। मुझे मिली जानकारी के मुताबिक प्रशासक और उसके सलाहकार जहां धीरे-धीरे नियम कायदों के साथ आगे बढ़ेंगे उस दौरान छह राज्यों में फैली पीएमसी बैंक की 137 शाखाओं को परिचालित करने के लिए हर महीने 27 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यानी रोजाना करीब एक करोड़ रुपये केवल बैंक को चलाने में लगेंगे। यह जमाकर्ताओं के धन को होने वाला नुकसान होगा। बैंक जितने लंबे समय तक इस स्थिति में रहेगा, उतना ज्यादा नुकसान इसे झेलना होगा क्योंकि बैंक का मूल काम यानी ऋण देने का काम एकदम रुका हुआ है।

हर बार जब आरबीआई किसी सहकारी बैंक को निर्देशन में रखता है तो ऐसा ही होता है। कैपोल सहकारी बैंक 31 मार्च, 2017 को ऐसे ही जॉम्बी बैंक में तब्दील हो गया और प्रति जमाकर्ता मात्र 3,000 रुपये की निकासी सीमा तय कर दी गई थी। बैंक जनवरी 2020 तक निर्देशन के अधीन रहेगा। रुपी कोऑपरेटिव बैंक भी 22 फरवरी 2013 को जॉम्बी बैंक में तब्दील हो गया। जमाकर्ता अपने पैसों को हाथ नहीं लगा सकते लेकिन बैंक के कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है। आरबीआई ने बैंक को अपवाद स्थितियों में कुछ पैसे जारी करने की छूट दी है।

103 वर्ष पुराने सीकेपी सहकारी बैंक को 2 मई 2012 को निर्देशन के अधीन रखा गया था। आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक मंडल ने अप्रैल 2015 तक बैंक को चलाया। इसके बाद नया बोर्ड चुना गया। जमाकर्ताओं ने अपने जमा के एक हिस्से को शेयर पूंजी में बदल लिया। बीते वर्षों के दौरान कई अवधि विस्तार के बाद बैंक अभी भी निर्देशन के अधीन है। हर कुछ महीने पर इसमें नए नाम जुड़ जाते हैं: द नीड ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक, कोल्हापुर का यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक, शिवम सहकारी बैंक, द सिटी कोऑपरेटिव बैंक, मुंबई, मराठा सहकारी बैंक, कराद जनता सहकारी बैंक आदि सभी आरबीआई के निर्देशन के अधीन हैं।

## सरकार क्यों जिम्मेदार है?

यह प्रक्रिया जमाकर्ताओं और उन अंशधारकों को प्रभावित करती है जो सबसे अधिक मानी रखते हैं। ज्यादातर मामलों मे वे उस धोखाधड़ी के शिकार हैं जो राजनेताओं ने अंजाम दी है। पीएमसी बैंक के मामले में ऐसा एक कारोबारी घराने ने किया। परंतु सहकारी बैंकों में लगातार विकृत पूंजीवाद, धोखाधड़ी और राजनीतिक प्रभाव के जरिये लाखों लोगों की बचत को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वित्त मंत्रालय और आरबीआई को निम्न बातों पर विचार करना चाहिए:

■ सरकार ने सहकारी बैंकों को खूब बढ़ावा दिया लेकिन इनके ग्राहकों को कभी ऐसे बैंकों से जुड़े अतिरिक्त जोखिम के बारे में नहीं बताया गया।

■ औसत हर चंद महीनों में एक सहकारी बैंक नाकाम हो जाता है। आरबीआई ने पिछली नाकामियों से कोई सबक नहीं सीखा है और उसने इस समस्या से निपटने का कोई उपाय नहीं किया।

■ आरबीआई ने कभी अपने ग्राहकों को नहीं बताया कि वह अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह इनका नियमन नहीं कर रहा है।

■ सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान कई सेवाएं देने की इजाजत दी गई। उदाहरण के लिए पीएमसी बैंक को अनिवासी खाते खोलने और विदेशी मुद्रा सौदों की इजाजत दी गई। वह बैंक गारंटी दे सकता था, वायदा कारोबार कर सकता था और क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकता था। ये सारी इजाजत आरबीआई ने संभवत: पूरी जांच परख के बाद दी होगी।

■ चुनिंदा सहकारी बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की इजाजत देकर या म्युचुअल फंड और बीमा बेचने की इजाजत देकर आरबीआई ने यह संकेत दिया कि वे ठीक ढंग से काम कर रहे हैं।

■ बैंकों को बिना स्रोत पर कर कटौती के ब्याज चुकाने की इजाजत देकर वित्त मंत्रालय ने कम आय वाले जमाकर्ताओं को ऐसे बैंकों की सावधि जमा में निवेश के लिए उत्साहित किया। जाहिर है लोग कर रिटर्न दाखिल करने और रीफंड लेने जैसी दिक्कतों से बचना चाहते थे।

■ आरबीआई के शहरी बैंक विभाग और सहकारी बैंकों के सलाहकार पदों की स्थिति ठीक नहीं है। वरिष्ठ आरबीआई अधिकारी इन सहकारी बैंकों की गतिविधियों के बारे में जानकारियां दबाए बैठे रहते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हीं बैंकों में सलाहकार भी बन जाते हैं। आखिर क्यों वरिष्ठ आरबीआई अधिकारी गड़बड़ियों वाली वित्तीय कंपनियों के बोर्ड में भी नजर आते हैं?

■ बीते 25 वर्ष से सहकारी बैंकों का हर जमा बीमा भुगतान सहकारी बैंकों से हुआ है जबकि अधिकांश प्रीमियम सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों से आया है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों को पता है कि सहकारी बैंक कैसे काम करते हैं और फिर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाई।

ये कुछ अहम मुद्दे हैं। स्थान की कमी के कारण विस्तार से नहीं लिख रहा हूं। आरबीआई नाकाम बैंकों से जिस तरह निपट रहा है उसे देखकर भी मैं चकित हूं। यदि किसी भी बैंक के पास अप्रत्यक्ष संपत्ति है तो उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। इसके लिए ऐसी नीतियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो उचित हों। सेवानिवृत्त केंद्रीय बैंकरों के बजाय इसका नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो सौदेबाजी में कुशल हो या अधिग्रहण या विलय को अंजाम दे सके। यदि ऐसी संपत्ति नहीं है तो फिर कुछ नहीं बचता। ऐसे बैंकों को हार्डकोर बैंकरों की आवश्यकता होती है जो ऋण वसूली, निवेश के नकदीकरण, जमाकर्ताओं की राशि चुकाने जैसे सख्त कदम उठाते हुए बैंक बंद कर सकें। चाहे जो भी हो गति और दिशा महत्त्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों उदासीन लग रहे हैं। वे तमाम नाकाम सहकारी बैंकों को जॉम्बी बैंक बना देंगे। यह भी एक वजह है जिसके चलते उन्हें अपनी निष्क्रियता की पूरी जिम्मेदारी लेकर जमाकर्ताओं को हर्जाना चुकाना चाहिए।

# मुवक्किल-वकील संवाद का विशेषाधिकार बने रहना जरूरी

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

मुवक्किल और वकील के बीच संवाद के सिलसिले को सुरक्षित रखने के वाजिब कारण हैं। हमारा समाज मानता है कि निष्पक्ष सुनवाई के बगैर सच की आलोचना नहीं की जा सकती है

**अगर** पिछले कुछ दिनों की मीडिया रिपोर्ट पर यकीन करें तो एक बार फिर जांच एजेंसियों ने वकीलों के कार्यक्षेत्र में दखल देने की कोशिश करते हुए उनके मुवक्किलों की जांच करने की अनुमति मांगी है। यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करने वाले बुनियादी नियमों में से एक का उल्लंघन करता है।

ऐसा कोई भी दूसरा पेशा नहीं है जिसमें भरोसा बनाए रखने की व्यवस्था कानून में ही की गई है। साक्ष्य संबंधी कानून के तहत एक वकील और मुवक्किल के बीच होने वाली गोपनीय बातचीत को साक्ष्य के तौर पर पेश करने से संरक्षा दी गई है। मुकदमे से जुड़ जाने के बाद वकील की उसके मुवक्किल के साथ होने वाली बातचीत को अभियोजन के दौरान साक्ष्य के तौर पर नहीं रखा जा सकता है। इस व्यावसायिक संबंध को यह विशेषाधिकार मिला है कि मुवक्किल को दी गई सलाह, तथ्यों के बारे में दी गई जानकारी और इससे संबंधित सारे कागजात को एक पवित्र संरक्षित जगह दी गई है और वहां पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

वैसे इस विशेषाधिकार को खुद मुवक्किल हटा सकता है और वकील से कह सकता है कि ऐसी विशेषाधिकृत सामग्री को जाहिर करे। इसी तरह, अगर वकील कानूनी सेवा नहीं दे रहा है और वह खुद ही कानून के उल्लंघन के किसी मामले में जांच का सामना कर रहा है तो फिर इस विशेषाधिकार का संरक्षण नहीं मिलेगा। यही वह बिंदु है जहां जांच एजेंसी वकील पर कानून के उल्लंघन में संलिप्त होने के आरोप लगाकर विशेषाधिकार को कमजोर कर सकती है।

हरेक समाज के अपने मानदंड एवं स्वीकृति स्तर होते हैं कि इन स्थानों में किस हद तक दखल दिया जा सकता है? किसी खास मामले में वकील द्वारा दी जाने वाली कानूनी सलाह की गुणवत्ता के बारे में जांच एजेंसियों द्वारा फैसला सुनाए जाने की मांग करने संबंधी खबर पर यकीन करें तो एक गंभीर अन्वेषण हस्तक्षेप आकार लेने वाला है। अगर अपने मुवक्किल को दी गई सलाह के सही या गलत होने को लेकर वकील के खिलाफ जांच होती है तो न केवल इस विशेषाधिकार का हनन होगा बल्कि गैर-अभियोजन हालात में भी वकील 'अफसरशाह' हो जाएंगे।

अफसरशाही के लिए 'भारत का लौह ढांचा' शब्दावली का इस्तेमाल निंदात्मक लहजे में किया जाता है। किसी मसले पर कोई स्पष्ट रुख लिए बगैर सुरक्षित ढंग से काम करने की प्रवृत्ति इसकी वजह है। पिछले कई वर्षों से अफसरशाही का झुकाव और उसकी क्षमता निर्णायक होने के मामले में क्षीण हुई है। रोजमर्रा के फैसलों में भी नजीरों का हवाला देने को भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच के दौरान सवालों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते फिलहाल पद पर बैठे अधिकारी डर से भरी जिंदगी जी रहे हैं।

निजी निवेश के क्षेत्र में उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां वकील पूंजी निवेश के बारे में मुवक्किलों को सलाह दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था के साथ आज केंद्रीय समस्या यह है कि निजी पूंजी सृजन को लेकर बुरी धारणा बनी हुई है। अगर निवेशकों को दी गई कानूनी सलाह पर सवाल उठते हैं तो इस नकारात्मक धारणा ने पूंजी निवेश के बारे में खूब हतोत्साहित किया। मुवक्किल और वकीलों के बीच संवाद के सिलसिले को सुरक्षित रखने के वाजिब कारण हैं। हमारा समाज मानता है कि निष्पक्ष सुनवाई के बगैर सच की आलोचना नहीं की जा सकती है। हमारे समाज की मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बगैर स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस मान्यता को साक्ष्य संबंधी कानून के अलावा संविधान में भी स्थान मिला हुआ है।

गलत काम में लिप्त रहने के आरोपी शख्स को एक ऐसी सुरक्षित जगह की निजता की जरूरत होती है जहां पर वह अभियोजन से जुड़े तथ्य एवं विवरणों के बारे में खुलकर बात कर सके। अगर ऐसी जगह नहीं दी जाती है तो केवल आरोप लगाने वालों का ही पक्ष नजर आएगा। उस स्थिति में किसी को गलत काम में लिप्त रहने का दोषी ठहराने के लिए केवल उस पर आरोप लगाने की ही जरूरत होगी। सच है कि अदालतों से लगातार यह कहा जा रहा है कि हिरासत में होने वाली पूछताछ जरूरी है क्योंकि संदिग्ध 'सहयोग नहीं कर रहा' है। 'सहयोग नहीं करना' आज 'अभियोग स्वीकार नहीं करने' का पर्याय हो गया है।

कानूनी पेशेवरों के बीच समस्यापरक नीतिशास्त्र हो सकता है लेकिन यह किसी भी पेशे और उसमें संलग्न लोगों के साथ ऐसा होता है। वकालत पेशे के नियमन का दायित्व रखने वाले संस्थान के समक्ष इसके नैतिक पहलू अनुशासनात्मक कार्यवाही का विषय हैं। यह काम वकीलों के ग्राहकों की जांच करने वाली जांच एजेंसियों का नहीं है।

वकीलों को लेकर तमाम मजाक किए जाते हैं और खुद पर हंसना एक आदत भी है। हरेक मुकदमे में एक विरोधात्मक स्वर और विचारों के प्रसार की गुंजाइश होती है जिन्हें दूसरे पक्ष के वकील जोरदार ढंग से चुनौती देते हैं। इससे वकीलों के भीतर खुद पर हंसने की क्षमता आती है। लेकिन अगर मुवक्किल के खिलाफ चल रही जांच के दौरान वकील को ही निशाना बनाया जाने लगे तो यह एक मनहूस समाज बनाने का ही मसाला होगा। एक संपूर्ण समाज का 'यूटोपिया' एक मरीचिका ही है क्योंकि इसे हासिल कर पाना मुश्किल है। लेकिन यह मतलब नहीं है कि पूरी तरह विरोधी समाज 'डिस्टोपिया' की तरफ कदम बढ़ाया जाए जिसे हासिल कर पाना बेहद आसान है।

## कानाफूसी

### मप्र में शक्ति संतुलन

मध्य प्रदेश में झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद कांतिलाल भूरिया मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सत्ता के चौथे केंद्र के रूप में उभरे हैं। नई चर्चा यह है कि उन्हें नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल यह पद मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास है और सिंधिया को इस पद का तगड़ा दावेदार माना जा रहा था। पिछले दिनों प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भूरिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग करते हुए कहा, 'प्रदेश में 15 वर्ष बाद कांग्रेस की सरकार बनी है। हमारे 32 विधायक आदिवासी बहुल आरक्षित सीटों से जीत कर आए हैं। भूरिया एक बड़ा नाम हैं और वह पहले भी तीन वर्ष तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं।'

### तैयारी आरंभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब यह समझ आ गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले दिन-रात काम करने वाली मीडिया टीम की कितनी अहमियत है। हाल ही में राज्य सरकार ने चार वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त किया है। दो मंत्री पहले से इस पद पर थे यानी अब सरकारी प्रवक्ताओं की तादाद बढ़कर छह हो गई है। हर मंत्री को क्रमश: प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यान रखना होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री के पास पहले से एक मीडिया सलाहकार हैं जिनकी नियुक्ति मार्च 2017 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तत्काल बाद की गई थी।

## आपका पक्ष

### स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कई कारण

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि दोनों राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी, लेकिन पार्टी का दावा गलत साबित हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी सभाओं में अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा जोर से उठाया, लेकिन स्थानीय मुद्दों के आगे यह मुद्दा कारगर साबित नहीं हो सका। महाराष्ट्र में 286 सीटों में भाजपा को 105 सीट और शिवसेना को 56 सीटें मिलीं। भाजपा को 17 सीट का नुकसान हुआ। इससे भाजपा तथा शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान होने लगी। हरियाणा में भाजपा को जजपा का समर्थन लेकर सरकार बनानी पड़ी। राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे अहम होते हैं और जब राज्य सरकार इन मुद्दों को सुलझाने में नाकामयाब होती है तो मतदाता दूसरे दलों को प्राथमिकता देते हैं। सुरक्षा, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है। लेकिन चुनावी सभा में ऐसे मुद्दे गायब हो जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा अपराध महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र का आर्थिक विकास अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सका है। राज्य के किसानों की दशा आज भी जस की तस बनी हुई है। सरकारी स्कूल उपेक्षित अवस्था में हैं। इसलिए चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है।

*निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर*

**महाराष्ट्र में शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना** *-पीटीआई*

### कृषि क्षेत्र में बजट बढ़ाने की जरूरत

देश गंभीर कृषि संकट के दौर से गुजर रहा है। गुजरात में पानी की कमी के कारण बुआई पर रोक लगी है, तो कहीं अधिक पैदावार की वजह से उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ ने हालत खराब कर रखी है। हरित क्रांति ने उपज तो बढ़ा दी लेकिन बदलते वक्त में कृषि में कई चुनौतियां भी पैदा कर दी है। अब ऐसी खोज की जरूरत है जो भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर पानी की कमी को देखते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ा सके। पिछले दो दशकों में देश में इससे संबंधित जीन क्रांति पर कोई काम नहीं हुआ है। घटते प्राकृतिक संसाधनों और बढ़ती आबादी की खाद्य सुरक्षा को देखते हुए कृषि क्षेत्र की चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसके अलावा अन्य समस्याओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देश का 53 प्रतिशत क्षेत्रफल असिंचित है। जरूरत के मुताबिक छोटे व सीमांत किसानों को न तो उन्नत बीज और न ही उन्नत तकनीक मिल रही है। कीटनाशक और एग्रो मशीनरी तैयार करने की कोशिश तो हुई है लेकिन इसके आगे की जीन तकनीक भारत में उपलब्ध नहीं है। करीब 40 दिन पहले तैयार गेहूं की दो-तीन प्रजातियों का कब्जा देश की दो-तिहाई खेती पर है। गेहूं की लगभग साढ़े चार सौ प्रजातियां तैयार की जा चुकी हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर की सिंचाई अधिक बार करनी करनी पड़ती है। अत: सरकार को नीतिगत स्तर पर कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल कृषि अनुसंधान पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.3 प्रतिशत खर्च हो रहा है। इसे बढ़ाकर एक प्रतिशत करने की आवश्यकता है।

*संगीता चौधरी, जयपुर*

**पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।**

## एमएसपी पर खरीद आज से

**राजस्थान** में मूंग, उड़द व सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद शुक्रवार से शुरू होगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि मूंग, उड़द व सोयाबीन की (एमएसपी) पर खरीद शुक्रवार, एक नवंबर को 250 केंद्रों पर शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से राज्य के किसानों द्वारा उपज बेचने के लिए पंजीयन किया जा रहा है और 30 अक्टूबर तक मूंग, उड़द, सोयाबीन व मूंगफली के लिए 2.09 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। केंद्र सरकार ने चारों जिंसों के लिए 9.63 लाख टन खरीद की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि 2 लाख 28,350 टन मूंग, 73,800 टन उड़द, 3 लाख 6,875 टन मूंगफली तथा 3 लाख 54,100 टन सोयाबीन की खरीद की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मूंगफली की खरीद सात नवंबर से की जाएगी। इसके लिए 72 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. नीरज पवन ने कहा कि खरीद के लिए 322 केंद्र स्थापित किए गए हैं। मूंग के लिए 150, मूंगफली के 72, उड़द के 61 व सोयाबीन के लिए 39 केंद्र हैं। किसानों से 7,050 रुपये प्रति क्विंटल मूंग, 5,090 रुपये प्रति क्विंटल मूंगफली, 5,700 रुपये रुपये प्रति क्विंटल उड़द व 3,710 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन की (एमएसपी) पर खरीद की जाएगी। *भाषा*

# महंगे प्याज में नरमी की उम्मीद

**सुशील मिश्र**
मुंबई, 31 अक्टूबर



■ देश के कई महानगरों के खुदरा बाजार में प्याज के दाम 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचे

■ दाम नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध और व्यापारियों के लिए इसकी स्टॉक सीमा तय की थी

बाजार में नई फसल की आवक शुरू होने के बावजूद प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। महज दो सप्ताह में थोक बाजार में प्याज के दाम दोगुने हो चुके हैं। मुंबई और दिल्ली सहित देश के ज्यादातर महानगरों के खुदरा बाजार में प्याज 60 रुपये किलोग्राम के आसपास बिक रहा है। सरकारी नीति और आवक बढ़ने की उम्मीद से कीमतों में अब गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है।

महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव में प्याज के दाम फिर से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ) के आंकड़ों के अनुसार लासलगांव में प्याज का औसत भाव 3,900 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,201 रुपये प्रति क्विंटल और न्यूनतम भाव 1,200 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया, जबकि महज दो सप्ताह पहले 17 अक्टूबर को यहां प्याज का औसत भाव 2,051 रुपये, अधिकतम 2,911 रुपये और न्यूनतम भाव 1,000 रुपये प्रति क्विंटल था। मुंबई में औसत भाव 3,900 रुपये और दिल्ली में औसत भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। पिछले महीने प्याज की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिली थी। लासलगांव में 19 सितंबर को अधिकतम भाव 5,100 रुपये और औसत भाव 4,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। दाम नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध के साथ-साथ व्यापारियों के लिए इसकी स्टॉक सीमा भी तय की थी। इसके बाद कीमतों में तेज गिरावट आई। 17 अक्टूबर तक प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली। 17 अक्टूबर को लासलगांव में औसत भाव गिरकर 2,051 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था लेकिन इसके बाद कीमतों में तेजी का दौर फिर शुरू हो गया जिसका असर देशभर की मंडियों में देखा जा रहा है।

खुदरा बाजार में कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर पार कर चुकी हैं। मुंबई में प्याज 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में यह 60 रुपये से कम ही दिखाया जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक मुंबई के खुदरा बाजार में प्याज का भाव 58 रुपये, दिल्ली में 55 रुपये, पटना में 50 रुपये और लखनऊ में 50 रुपये प्रति किलोग्राम चल रहा है। सरकारी आंकड़ों में एक बात और देखने को मिल रही है कि थोक बाजार में प्याज के दाम भले ही कम हुए थे, लेकिन खुदरा बाजार में पिछले दो महीने के दौरान प्याज के दामों में खास गिरावट नहीं हुई है।

प्याज की नई फसल तैयार होने के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी पर कारोबारियों का कहना है कि बीच में जो दाम गिरे थे, वे सरकार के दबाव के कारण गिरे थे क्योंकि महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान था और उसके दो दिन पहले से ही थोक बाजार में कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं। सरकार का पूरा ध्यान थोक बाजार पर था इसीलिए खुदरा बाजार में प्याज के दामों में खास गिरावट नहीं दिखाई दी। हालांकि अब कीमतों में ज्यादा दिन तेजी नहीं रहने वाली है क्योंकि नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। दीवाली के समय मंडियों में छुट्टी और किसानों की व्यस्तता के कारण आवक कमजोर थी जो अब धीरे-धीरे सही होगी। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्य उत्पादक राज्यों - महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से आपूर्ति प्रभावित होने और फसल को नुकसान पहुंचने के कारण प्याज सहित दूसरी सब्जियों के दामों में तेजी आई है। गर्मियों यानी खरीफ की नई फसल की आवक से आगामी दिनों में प्याज की कीमतों में कमी आएगी। अगले दस दिन में स्थिति सुधरेगी और कीमतें कुछ नीचे आएंगी। दिल्ली में प्याज की कीमतें काबू करने के लिए सरकार ने मदर डेरी की सफल दुकानों, सहकारिता नेफेड और एनसीसीएफ के जरिये आपूर्ति बढ़ाई है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सफल की 400 दुकानों पर प्याज 23.90 रुपये किलो के भाव पर बेचा जा रहा है। सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज उपलब्ध करा रही है।

# सराफा बैंक शुरू करने का सुझाव

**दिलीप कुमार झा**
मुंबई, 31 अक्टूबर

**स्वर्ण** खनिकों के संगठन विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) ने भारत सरकार को मुख्य बैंकिंग प्रणाली से सराफा कारोबार के जरिये सराफा बैंकिंग शुरू करने की सलाह दी है ताकि इस कारोबार में पारदर्शिता लाई जा सके और इस मूल्य श्रृंखला में 50 करोड़ डॉलर की संभावना तक पहुंच बनाई जा सके। फिलहाल बैंक सोने का आयात कर रहे हैं और स्वर्ण धातु ऋण के रूप में उधार दे रहे हैं। इस प्रकार सराफा बैंकिंग इस कारोबार की तरह कुछ लोगों तक ही सीमित है। हालांकि आगे चलकर जब सरकार स्वर्ण नीति की घोषणा करेगी और इसे लागू करेगी तथा स्पॉट एक्सचेंज सहित और सुधारों को लागू करेगी तो बैंकों की भूमिका का भी विस्तार होना चहिए और बैंकों को केवल बिक्री करने की अपेक्षा सोने की खरीद की भी अनुमति मिलनी चाहिए।

डब्ल्यूजीसी के अनुसार सराफा बैंक को खुदरा-ग्रामीण ऋण, थोक बैंकिंग और ऋण तथा कॉरपोरेट और संस्थागत कारोबारी बैंकों के रूप में कारोबारी मंच पर काम करने, अपने स्वामित्व वाले व्यापार, संरचनात्मक उत्पादों और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड शुरू करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में सराफा बैंकिंग सराफा क्षेत्र में इन सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए, स्वर्ण आयात और ऋण देने का काम करने के लिए एक अनुभाग के रूप में तब्दील हो जाएगी। डब्ल्यूजीसी ने 'भारत में सराफा बैंकिंग की जरूरत' नामक रिपोर्ट में सराफा बैंक को एक ऐसे बैंक के रूप में परिभाषित किया है जो वित्तपोषण की पेशकश करते हुए मानकीकृत सराफा के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद की सुविधा देता है तथा सराफा बाजार में भागीदारों को बिक्री और व्यापारिक सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार यह बैंक शुद्ध रूप से सोने से जुड़ी सेवाएं जैसे बचत खाता, सावधि जमा, संचय योजना, जीवन बीमा, अंतर-बैंक ऋण, पेपर गोल्ड बॉन्ड, स्वर्ण मद्रीकरण योजना, स्वर्ण धातु ऋण, कच्चे सोने का वित्त पोषण और सराफा के एवज में कर्ज आदि प्रदान करेगा। फिलहाल दुनिया में सराफा बैंकिंग परिचालन के जरिये गोल्ड बैंकिंग से प्रति वर्ष (2017 में) 1.5-1.8 अरब डॉलर के राजस्व का सृजन होता है जिसमें वित्तपोषण गतिविधियों के ब्याज से प्राप्त आय तथा बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों का ब्रोकरेज और शुल्क से प्राप्त आय भी शामिल रहती है।

डब्ल्यूजीसी (भारत) के प्रबंध निदेशक सोमसुदंरम पीआर ने कहा कि भारत में सराफा बैंकिंग की शुरुआत इन दो में से किसी एक रास्ते पर होनी चाहिए - या तो सराफा बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों से अलग नई संस्था के रूप में प्रबंधित किया जाए या फिर भारतीय रिजर्व बैंक चुनिंदा वाणिज्यिक बैंकों को विशेष लाइसेंस प्रदान करे। परिचालन के दृष्टिकोण से सराफा बैंकिंग वाणिज्यिक बैंकिंग के समान ही होती है।

## 'स्वर्ण माफी योजना का कोई प्रस्ताव नहीं'




**सरकार** सोने के रूप में जमा अघोषित संपत्ति का पता लगाने के लिए स्वर्ण माफी योजना पेश करने पर विचार नहीं कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सरकार माफी योजना ला सकती है। यह लोगों और इकाइयों को बिना मुकदमे के सोने में अपने निवेश का खुलासा करने की अनुमति देगा। सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ऐसी किसी भी स्वर्ण माफी योजना पर विचार नहीं कर रहा है जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बजट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आमतौर पर बजट से पहले इस तरह के कयास सामने आते रहते हैं। मीडिया में आ रही खबरों में कहा गया है कि नई आम माफी योजना से सोने के जमाखोरों को कालेधन से किए गए निवेश को वैध बनाने का मौका मिलेगा। *भाषा*

## अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

| As on Oct 31 | International Price | International %Chg# | Domestic Price | Domestic %Chg# |
|---|---|---|---|---|
| METALS ($/tonne) | | | | |
| Aluminium | 1,746.5 | -1.7 | 1,917.4 | -6.4 |
| Copper | 5,883.0 | -0.7 | 6,132.8 | -6.0 |
| Nickel | 16,900.0 | 17.7 | 17,341.0 | 19.9 |
| Lead | 2,255.5 | 13.8 | 2,157.1 | 0.3 |
| Tin | 16,800.0 | -2.7 | 17,764.0 | -4.5 |
| Zinc | 2,563.5 | 5.7 | 2,735.1 | -1.0 |
| Gold ($/ounce) | 1,508.2* | 6.7 | 1,694.4 | 7.8 |
| Silver ($/ounce) | 18.1* | 11.0 | 20.5 | 10.9 |
| ENERGY | | | | |
| Crude Oil ($/bbl) | 59.8* | -6.7 | 61.1 | -3.7 |
| Natural Gas ($/mmBtu) | 2.7* | 22.0 | 2.7 | 20.8 |
| AGRI COMMODITIES ($/tonne) | | | | |
| Wheat | 181.3 | 1.2 | 303.1 | 0.6 |
| Maize | 182.2* | -3.3 | 300.7 | -3.8 |
| Sugar | 339.7* | 4.8 | 495.1 | 4.2 |
| Palm oil | 582.5 | 13.1 | 924.9 | 11.6 |
| Rubber | 1,435.7* | -28.0 | 1,762.3 | -18.4 |
| Coffee Robusta | 1,262.0* | -5.7 | 1,910.3 | -16.6 |
| Cotton | 1,438.5 | 3.2 | 1,617.2 | -7.7 |

* As on Oct 31, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 70.9& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

## एमसीएक्स

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|---|---|---|
| **Agri commodity** | | |
| Cotton | 42.0 | 14393 |
| Oil and Oilseeds | 208.9 | 81662 |
| Spices | 1.3 | 17 |
| **Metal (Oct 30)** | | |
| Metal- non ferrous | 4079.7 | 69024 |
| Metal- precious | 9361.8 | 420 |
| **Oil and gas(Oct 30)** | | |
| Gas | 3468.3 | 18173 |
| Oil | 11982.3 | 1973 |

## एनसीडीईएक्स

| Name | Tovr (₹ Cr) | OI(000) |
|---|---|---|
| **Agri commodity** | | |
| Cotton | 175.9 | 95834 |
| Grains | 288.9 | 99910 |
| Oil and Oilseeds | 646.5 | 384605 |
| Others | 227.7 | 65805 |
| Pulses | 136.4 | 79860 |
| Spices | 92.4 | 37935 |

## एमसीएक्स बढ़ा/घटा

| Name (Maturity) | Close | Day* |
|---|---|---|
| **Gainers (* % Change)** | | |
| Nickel (Oct 31) | 1237.2 | 1.7 |
| Gold Mini (Nov 05) | 38369.0 | 0.7 |
| Kapas (Apr 30) | 1092.5 | 0.6 |
| Gold Guinea (Oct 31) | 30923.0 | 0.6 |
| Aluminium (Oct 31) | 130.2 | 0.5 |
| Aluminium Mini (Oct 31) | 130.2 | 0.5 |
| **Losers (* % Change)** | | |
| Gold Petal (Oct 31) | 3931.0 | -5.0 |
| Cardamom (Nov 15) | 2434.1 | -3.7 |
| Crude Oil Mumbai (Nov 19) | 3879.0 | -2.0 |
| Crude Oil (Nov 19) | 3880.0 | -2.0 |
| Lead (Oct 31) | 165.7 | -1.0 |
| Lead Mini (Oct 31) | 158.5 | -1.0 |

## एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

| Name (Maturity) | Close | Day* |
|---|---|---|
| **Gainers (* % Change)** | | |
| CottonSeed Oil-Akola (Dec 20) | 2267.0 | 3.4 |
| Coriander-Kota (Nov 20) | 6813.0 | 2.7 |
| Soyabean Indore (Nov 20) | 3863.0 | 1.9 |
| Moong-Mertacity (Nov 20) | 6740.0 | 1.7 |
| GuarGum 5T-Jodhpur (Nov 20) | 7704.0 | 1.5 |
| Guar Seed 10 (Nov 20) | 4074.0 | 1.4 |
| Chana-Bikaner (Nov 20) | 4455.0 | 1.1 |
| Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30) | 1093.0 | 0.6 |
| Barley Jaipur (Nov 20) | 2110.0 | 0.1 |
| **Losers (* % Change)** | | |
| CastorSeed New-Disa (Nov 20) | 4482.0 | -0.5 |
| Jeera Unjha (Nov 20) | 16405.0 | -0.5 |
| Ref Soy Oil-IDR-2016 (Nov 20) | 771.4 | -0.4 |

## एमसीएक्स बढ़त/छूट

| Name (Maturity) | Futures | Prem/Dis |
|---|---|---|
| **Premium over spot price** (In %) | | |
| Cotton-Rajkot (Oct 31) | 19500.0 | 3.1 |
| Lead Mum (Oct 31) | 165.7 | 2.1 |
| Gold Petal-Mumbai (Oct 31) | 3931.0 | 1.4 |
| Nickel Mumbai (Oct 31) | 1237.2 | 0.6 |
| **Discount over spot price** (In %) | | |
| Menthol Oil Chandaus (Oct 31) | 1208.2 | -11.5 |
| Aluminium Mum (Oct 31) | 130.2 | -6.6 |
| Alumini-Mumbai (Oct 31) | 130.2 | -6.6 |
| Zinc Mumbai (Oct 31) | 188.2 | -4.4 |
| Kapas Surendranagar (Feb 28) | 1043.0 | -4.3 |
| Zinc Mini Mumbai (Oct 31) | 188.8 | -4.1 |
| Cardamom Vandanmedu (Nov 15) | 2434.1 | -3.6 |
| Lead Min Mumbai (Oct 31) | 158.5 | -2.3 |

## एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

| Name (Maturity) | Futures | Prem/Dis |
|---|---|---|
| **Premium over spot price** (In %) | | |
| Paddy-Basmati-Karnal (Nov 20) | 3382.0 | 8.2 |
| Moong-Merta City (Nov 20) | 6740.0 | 3.1 |
| 29 mm Cotton-Rajkot (Nov 20) | 19030.0 | 0.4 |
| **Discount over spot price** (In %) | | |
| Maize-Sangli (Nov 20) | 1990.0 | -12.7 |
| Jeera Unjha (Nov 20) | 16405.0 | -1.4 |
| Turmeric Nizamabad (Nov 20) | 6130.0 | -1.1 |
| Coriander-Kota (Nov 20) | 6813.0 | -1.1 |
| Soy Bean Indore (Nov 20) | 3863.0 | -0.7 |
| Barley Jaipur (Nov 20) | 2110.0 | -0.6 |
| Crude Palm Oil Kandl (Oct 31) | 590.5 | -0.5 |
| Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Nov 20) | 7704.0 | -0.5 |

## कल का हाजिर भाव

### औद्योगिक

| Metals | ..............Mumbai |
|---|---|
| Aluminium utensil scrap /kg | 97.....................(97) |
| Aluminium ingots /kg | 136.....................(136) |
| Brass sheet cutting /kg | 308.....................(305) |
| Brass utensil scraps/kg | 292.....................(290) |
| Copper heavy scrap /kg | 400.....................(399) |
| Copper utensil scraps/kg | 376.....................(376) |
| Copper wire bar /kg | 435.....................(434) |
| Lead ingots /kg | 153.....................(153) |
| Nickel Cathodes /kg | 1230.....................(1240) |
| Tin slabs /kg | 1260.....................(1270) |
| Zinc slabs /kg | 194.....................(191) |

Source:Bombay Metal Exchange

| Cotton | ..............Mumbai |
|---|---|
| Bengal Deshi /Qtl | 10798.................(10798) |
| Jaydhar /Qtl | 10404.................(10320) |
| Shankar- 6 /Qtl | 11867.................(12007) |

Source:Cotton Association of India

| Oil | ..............Mumbai |
|---|---|
| Castor FSG /10kg | 957.....................(955) |
| Castor Comm /10kg | 947.....................(945) |
| Ricebran oil/10kg | 760 .........................(-) |
| Groundnut oil /10kg | 1020..................(1020) |
| Linseed oil /10kg | 810 .........................(-) |
| Karanji /10kg | 800 .........................(-) |
| Palm oil /10kg | 670.....................(665) |
| Sunflower exp ref /10kg | 810.....................(808) |
| Sunflower oil exp /10kg | 765.....................(770) |
| Soyabean ref / 10kg | 760.....................(755) |

Source:Bombay Commodity Exchange

### सॉफ्ट

| Sugar | ..............Mumbai |
|---|---|
| Mumbai M-30 /Qtl | 3452-3572 .........(3452-3570) |

Source:Bombay Sugar Merchants Association

### ऊर्जा

| Crude Brent-$/Barrel | ........................... |
|---|---|
| NYSE Crude | 54.9.................(55.06) |
| Brent Crude (UK) | 60.17 ..................(60.1) |
| Brent Crude (WTI) | 55.06.................(55.06) |
| NYSE Natural Gas-$/Mmbtu | 2.72...................(2.69) |
| Furnace/ 180 Cst &/bbl | 316.64 ...............(311.4) |
| Naptha spot /Rs/MT | 45170.................(45170) |
| LSHS spot/ M.T. | 36150.................(36150) |
| Furnace Oil spot/ K.L. | 33950.................(33950) |

Source:Petroleum Bazaar.com

### सर्राफा

| Gold | ..............Mumbai |
|---|---|
| Standard (99.50 Purity) /10 gms | 38641.................(38317) |
| Pure (99.90 Purity) /10 gms | 38796.................(38471) |
| Silver.999/ kg | 46775.................(46265) |

Source:India Bullion & Jewellers Association

### @SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

| Commodity | Unit | PClose | Price (₹.) Close |
|---|---|---|---|
| 29 mm Cotton-Rajkot (N) | 1 B | 18961.25 | 18961.25 |
| Alumini-Mumbai (M) | 1 K | 138.50 | 139.35 |
| Bajra-Delhi (N) | 1 Q | 1950.00 | 1800.00 |
| Barley Jaipur (N) | 1 Q | 2115.75 | 2123.50 |
| Brass-Jamnagar (M) | 1 K | 297.00 | 291.00 |
| Cardamom-Vand. (I) | 1 K | 2607.00 | 2575.00 |
| Castor Seed Disa (N) | 1 Q | 4489.30 | 4489.30 |
| Castor Seed-Kadi (N) | X | 4500.00 | 4500.00 |
| Chana Bikaner (N) | 1 Q | 4358.00 | 4397.15 |
| Chana Delhi (N) | 1 Q | 4555.25 | 4575.00 |
| Chana-Akola (N) | X | 4487.50 | 4475.00 |
| Copra-Calicut (I)* | 1 Q | 10486.00 | 10486.00 |
| Coriander-Gondal (N) | X | 6405.00 | 6405.00 |
| Coriander-Jaipur (N) | X | 6868.75 | 6875.00 |
| Coriander-Kota (N) | 1 Q | 6847.45 | 6888.30 |
| Cotton Seed Oilck Ak (N) | 1 Q | 3241.55 | 3213.90 |
| Cotton Seed Oilck Ka (N) | 1 Q | 2914.60 | 2914.60 |
| Cotton-Kadi (N) | 1 B | 18811.85 | 18827.80 |
| CPO-Kandla (M) | 10 K | 580.90 | 583.00 |
| Crude Palm Oil Kandl (N) | 10 K | 590.40 | 593.65 |
| Diamond 0.3 - Surat (I) | 1 CT | 866.40 | 866.40 |
| Diamond 0.5-Surat (I) | 1 CT | 1534.90 | 1534.90 |
| Diamond 1-Surat (I) | 1 CT | 3444.85 | 3444.85 |
| Gold Ahm (M) | 10 G | 38630.00 | 38650.00 |
| Gold Guinea-Ahmedaba (M) | 8 G | 31028.00 | 31044.00 |
| Gold Petal-Mumbai (M) | 1 G | 3846.00 | 3878.00 |
| Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N) | X | 7684.10 | 7743.75 |
| Guar Seed 10 MT-Jodh (N) | 1 Q | 4047.50 | 4081.75 |
| Guarseed-Jodhpur (I) | 1 Q | 4050.00 | 4038.00 |
| Gur Muzaffar Nagar (N) | 40 K | 1078.75 | 1070.45 |
| Isabgulseed-Unjha (I) | 1 K | 89.00 | 89.00 |
| Jeera Jodhpur-Jodhpu (N) | X | 17000.00 | 17100.00 |
| Jeera Unjha (N) | 1 Q | 16643.75 | 16643.75 |
| Kapas Kadi-Kadi (N) | X | 1128.35 | 1087.50 |
| Kapas-Rajkot (N) | X | 1112.50 | 1112.50 |
| Lead Mum (M) | 1 K | 163.70 | 162.30 |
| Maize Kharif-Nizamab (N) | X | 2050.00 | 2150.00 |
| Maize Rabi-Gulabbagh (N) | 1 | 2126.10 | 2134.40 |
| Maize-Erode (N) | X | 2302.25 | 2287.00 |
| Maize-Feed/Ind-Delhi (N) | 1 Q | 2150.00 | 2100.00 |
| Maize-Sangli (N) | X | 2296.00 | 2278.35 |
| Moong-Merta City (N) | 1 Q | 6512.50 | 6537.90 |
| Mustardseed Alwar (N) | 20 K | 4411.25 | 4372.65 |
| Nickel Mumbai (M) | 1 K | 1241.30 | 1230.00 |
| Paddy-Basmati-Karnal (N) | X | 3150.00 | 3125.00 |
| Paddy-Basmati-Karnal (I) | 1 Q | 3371.00 | 3371.00 |
| Pepper-Ernakulam (I) | 1 K | 313.00 | 313.00 |
| Pepper-Kochi (N) | 1 Q | 31733.35 | 32000.00 |
| Rape mustards-Patan (I) | 20 K | 724.00 | 724.00 |
| Rapeseed Must.Seed (N) | X | 2098.35 | 2113.00 |
| RBD Palm Olein Kakin (N) | 10 K | 651.15 | 656.00 |
| Ref Soya Oil Indore (N) | 10 K | 767.15 | 769.15 |
| Ref Soya Oil Mum (N) | 10 K | 758.95 | 762.55 |
| Ref Soya Oil Nagpur (N) | 10 K | 775.00 | 780.00 |
| Rubber-Kochi (N) | 1 Q | 12400.00 | 12500.00 |
| Rubber-Kochi/Ernak. (I) | 1 Q | 12385.00 | 12475.00 |
| Sack-Kolkata (I)* | 100 NOS | 4389.00 | 4389.00 |
| Silver M-Ahemdabad (M) | 1 K | 46820.00 | 46749.00 |
| Soy Bean Indore (N) | 1 Q | 3850.00 | 3892.00 |
| Soy Bean Kota (N) | 1 Q | 3769.00 | 3800.15 |
| Soy Bean Nagpur (N) | 1 Q | 3757.20 | 3832.95 |
| Soy Bean-Akola (N) | X | 3700.00 | 3794.00 |
| Soymeal Indore (N) | 1 T | 32000.00 | 32267.00 |
| Soyoil-Indore (I) | 10 K | 765.80 | 767.40 |
| Steel Long-Ghaziabad (I) | 1 T | 27880.00 | 27800.00 |
| Steel Long-MGG (I) | 1 T | 28150.00 | 28450.00 |
| Steel Long-Raipur (I) | 1 T | 25670.00 | 25670.00 |
| Sugar M Delhi (N) | 1 Q | 3380.00 | 3375.00 |
| Sugar M Grade-Kanpur (N) | 1 Q | 3504.75 | 3478.25 |
| Sugar M Grade-Kolhap (N) | 1 Q | 3310.50 | 3309.60 |
| Sugar M Kolkatta (N) | 1 Q | 3559.50 | 3566.65 |
| Sugar M Muzaff (N) | 1 Q | 3376.25 | 3368.75 |
| Sugar S-Kolhapur (N) | 1 Q | 3150.00 | 3147.50 |
| Turmeric Nizamabad (N) | 1 Q | 6150.00 | 6200.00 |
| Wheat Delhi (N) | 1 Q | 2228.35 | 2249.15 |
| Wheat Kota (N) | 1 Q | 2092.20 | 2119.55 |
| Wheat New Indore (N) | 1 Q | 2200.00 | 2200.00 |
| Wheat New Kanpur (N) | 1 Q | 2077.50 | 2080.00 |
| Wheat New-Rajkot (N) | 1 Q | 2171.65 | 2171.65 |
| Yellow Peas Mum (N) | 1 Q | 4875.00 | 4859.65 |
| Zinc Mumbai (M) | 1 K | 198.75 | 196.90 |

* as on Oct 30, 19

*(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices*

## जिंस वायदा




| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| **DAY SESSION** | | | | |
| **दिवस सत्र (गुरुवार)** | | | | |
| **कृषि जिंस** | | | | |
| **Cotton** | | | | |
| **Cotton MCX(1 B)** | | | | |
| Oct 31 | 19570, 20100, 19100, 19500 | 612 | 105 | 17 |
| Nov 29 | 19450, 19550, 19430, 19500 | 2470 | 440 | 9260 |
| Dec 31 | 19460, 19510, 19440, 19490 | 472 | 99 | 4554 |
| Jan 31 | 19650, 19650, 19650, 19650 | 09 | 2 | 136 |
| Mar 31 | 19590, 19590, 19590, 19590 | 04 | 1 | 09 |
| **CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Dec 20 | 2188, 2280.5, 2188, 2267 | 55640 | 3342 | 57330 |
| Jan 20 | 2140, 2226, 2140, 2210 | 16300 | 1071 | 26640 |
| Feb 20 | 2147, 2200, 2142, 2199.5 | 1610 | 131 | 7540 |
| Mar 20 | 2142, 2211, 2142, 2211 | 80 | 8 | 560 |
| **Kapas MCX(20 K)** | | | | |
| Apr 30 | 1088, 1094, 1087.5, 1092.5 | 200 | 46 | 384 |
| **Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)** | | | | |
| Apr 30 | 1086, 1094, 1086, 1093 | 573 | 361 | 3764 |
| **Grains** | | | | |
| **Barley Jaipur NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Nov 20 | 2110, 2110, 2110, 2110 | 10 | 1 | 90 |
| **Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)** | | | | |
| Nov 20 | 4021, 4080, 4016, 4074 | 40240 | 2554 | 43990 |
| Dec 20 | 4061, 4122.5, 4061, 4117.5 | 30120 | 1789 | 50540 |
| Jan 20 | 4115, 4166.5, 4115, 4136.5 | 530 | 34 | 510 |
| **Oil and Oilseeds** | | | | |
| **CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)** | | | | |
| Nov 20 | 4516, 4530, 4480, 4482 | 5580 | 391 | 47665 |
| Dec 20 | 4586, 4600, 4554, 4562 | 4700 | 242 | 34955 |
| Jan 20 | 4616, 4616, 4602, 4604 | 65 | 9 | 6600 |
| Feb 20 | 4600, 4620, 4558, 4600 | 840 | 34 | 1815 |
| **Crude Palm Oil MCX(10 K)** | | | | |
| Oct 31 | 580.7, 582.5, 579.4, 582.4 | 8860 | 353 | 4040 |
| Nov 29 | 590, 596.1, 588.1, 590.1 | 14800 | 910 | 58980 |
| Dec 31 | 597, 602, 594.6, 597.1 | 6680 | 424 | 14050 |
| Jan 31 | 597.1, 602.5, 595, 597.5 | 70 | 7 | 4100 |
| **Mentha Oil MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 1207, 1218, 1203.5, 1208.2 | 8.28 | 23 | 95.04 |
| Nov 29 | 1219.8, 1221.6, 1210, 1217.1 | 213.12 | 496 | 382.32 |
| Dec 31 | 1219.9, 1227.8, 1219.9, 1224.4 | 18.36 | 42 | 14.4 |
| **Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Nov 20 | 4299, 4323, 4294, 4306 | 15990 | 1108 | 35470 |
| Dec 20 | 4275, 4300, 4268, 4279 | 9000 | 629 | 20260 |
| Jan 20 | 4272, 4285, 4272, 4280 | 100 | 8 | 290 |
| **Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)** | | | | |
| Nov 20 | 771, 773.75, 768.5, 771.35 | 10850 | 688 | 26910 |
| Dec 20 | 776.65, 779.4, 773, 775 | 8360 | 548 | 20190 |
| Jan 20 | 779.2, 781, 777.1, 778.05 | 780 | 52 | 1560 |
| **Soyabean Indore NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Nov 20 | 3795, 3880, 3783, 3863 | 38450 | 2765 | 61100 |
| Dec 20 | 3824, 3906, 3810, 3892 | 31870 | 2434 | 87480 |
| Jan 20 | 3845, 3937, 3845, 3923 | 12060 | 1006 | 32460 |
| Feb 20 | 3900, 3978, 3890, 3963 | 4050 | 287 | 7410 |
| Mar 20 | 3980, 3980, 3980, 3980 | 120 | 9 | 290 |
| **Others** | | | | |
| **GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)** | | | | |
| Nov 20 | 7604, 7720, 7604, 7704 | 14380 | 1368 | 19380 |
| Dec 20 | 7707, 7835, 7701, 7821 | 14940 | 1352 | 45910 |
| Jan 20 | 7840, 7920, 7840, 7900 | 145 | 15 | 515 |
| **Pulses** | | | | |
| **Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)** | | | | |
| Nov 20 | 4408, 4461, 4408, 4455 | 16830 | 1150 | 35570 |
| Dec 20 | 4433, 4468, 4433, 4461 | 12380 | 827 | 37670 |
| Jan 20 | 4452, 4478, 4450, 4471 | 1410 | 122 | 4180 |
| Mar 20 | 4474, 4475, 4465, 4475 | 30 | 3 | 20 |
| **Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)** | | | | |
| Nov 20 | 6735, 6740, 6735, 6740 | 50 | 2 | 825 |
| **Spices** | | | | |
| **Cardamom MCX(1 K)** | | | | |
| Nov 15 | 2500, 2500, 2425.7, 2434.1 | 2.5 | 21 | 3.5 |
| Dec 13 | 2350, 2350, 2275.8, 2289.1 | 2.2 | 20 | 7.9 |
| Jan 15 | 2345.3, 2345.3, 2301.2, 2312.5 | 0.6 | 6 | 4.1 |
| Feb 14 | 2326.3, 2326.3, 2326.3, 2326.3 | 0.2 | 2 | 0.8 |
| Mar 13 | 2425, 2425, 2425, 2425 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| **Coriander-Kota NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Nov 20 | 6620, 6835, 6620, 6813 | 6240 | 436 | 14020 |
| Dec 20 | 6662, 6837, 6650, 6812 | 3190 | 246 | 8100 |
| Jan 20 | 6795, 6885, 6795, 6873 | 120 | 12 | 180 |
| **Jeera Unjha NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Nov 20 | 16490, 16575, 16360, 16405 | 699 | 214 | 2019 |
| Dec 20 | 16350, 16510, 16350, 16430 | 576 | 174 | 786 |
| **Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)** | | | | |
| Nov 20 | 6144, 6168, 6114, 6130 | 495 | 95 | 5060 |
| Dec 20 | 6170, 6180, 6128, 6150 | 595 | 93 | 7505 |
| Apr 20 | 6490, 6550, 6490, 6550 | 70 | 13 | 235 |
| **धातु** | | | | |
| **Metal- non ferrous** | | | | |
| **Aluminium MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 130.2, 134.75, 129.3, 131.25 | 985 | 189 | 2295 |
| Nov 29 | 132.3, 132.45, 131.5, 132.05 | 8200 | 1354 | 14570 |
| Dec 31 | 134.55, 134.55, 133.75, 134.05 | 560 | 65 | 515 |
| **Aluminium Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 130.4, 130.4, 129.6, 129.65 | 19 | 7 | 79 |
| Nov 29 | 132.1, 132.45, 131.5, 132.05 | 3797 | 2761 | 4815 |
| Dec 31 | 134.55, 134.7, 133.8, 134 | 49 | 49 | 81 |
| **Copper MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 440.05, 449.8, 435, 435.8 | 315 | 123 | 622.5 |
| Nov 29 | 443.95, 443.95, 440.25, 440.8 | 19395 | 6090 | 17677.5 |
| Dec 31 | 448.1, 448.35, 445.5, 445.95 | 280 | 109 | 810 |
| **Lead MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 164.5, 169.9, 161, 165.1 | 300 | 51 | 230 |
| Nov 29 | 157.7, 157.95, 157.25, 157.4 | 7805 | 1352 | 9640 |
| Dec 31 | 157.6, 157.8, 157.4, 157.6 | 85 | 13 | 190 |
| **Lead Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 157.8, 168, 157.8, 164.5 | 12 | 12 | 3 |
| Nov 29 | 157.7, 157.7, 157.3, 157.45 | 2705 | 2200 | 2512 |
| Dec 31 | 157.7, 157.95, 157.6, 157.65 | 61 | 60 | 135 |
| **Nickel MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 1246, 1250, 1200, 1248.5 | 50.75 | 140 | - |
| Nov 29 | 1207.9, 1209.1, 1191.3, 1196.6 | 4184.25 | 12679 | 2616.25 |
| Dec 31 | 1202, 1205, 1180.2, 1190.8 | 178.5 | 111 | 141 |
| **Zinc MCX(1 K)** | | | | |




| Maturity | Open, High Low Close | Qty | Trds | OI |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | 189.9, 189.9, 187, 188.7 | 80 | 9 | 1150 |
| Nov 29 | 188.7, 188.9, 188, 188.35 | 17475 | 2705 | 14020 |
| Dec 31 | 190.35, 190.35, 190, 190.1 | 165 | 27 | 520 |
| **Zinc Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 188.05, 193.3, 187, 187.35 | 26 | 17 | 141 |
| Nov 29 | 189.1, 189.1, 188.05, 188.35 | 5077 | 3963 | 3593 |
| Dec 31 | 190.75, 190.75, 190, 190.25 | 91 | 80 | 256 |
| **Metal- precious** | | | | |
| **Gold MCX(10 G)** | | | | |
| Dec 05 | 38105, 38378, 38037, 38353 | 6.91 | 5937 | 17.01 |
| Feb 05 | 38261, 38545, 38217, 38527 | 0.38 | 316 | 5.02 |
| **Gold Guinea MCX(8 G)** | | | | |
| Oct 31 | 31100, 31200, 30900, 31192 | 0 | 19 | 0 |
| Nov 29 | 30461, 30650, 30461, 30620 | 0 | 228 | 0 |
| Dec 31 | 30533, 30666, 30525, 30653 | 0 | 31 | 0 |
| **Gold Mini MCX(10 G)** | | | | |
| Nov 05 | 38300, 38664, 38300, 38631 | 0.13 | 593 | 0.27 |
| Dec 05 | 38109, 38360, 38040, 38334 | 0.96 | 7973 | 0.88 |
| Jan 03 | 38125, 38388, 38105, 38372 | 0.06 | 515 | 0.13 |
| **Gold Petal MCX(1 Gm)** | | | | |
| Oct 31 | 3931, 4020, 3931, 3942 | 0 | 118 | 0 |
| Nov 29 | 3845, 3865, 3842, 3864 | 0 | 1150 | 0.01 |
| Dec 31 | 3846, 3874, 3843, 3863 | 0 | 93 | 0 |
| Jan 31 | 3760, 3760, 3760, 3760 | 0 | 1 | 0 |
| **Silver MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 05 | 46061, 46744, 46021, 46685 | 415.83 | 11218 | 327.75 |
| Mar 05 | 46986, 47564, 46928, 47504 | 9.54 | 256 | 36.99 |
| **Silver Micro MCX(1 K)** | | | | |
| Nov 29 | 46230, 46750, 46083, 46685 | 33.8 | 23558 | 23.63 |
| Feb 28 | 46927, 47561, 46920, 47517 | 2.08 | 1590 | 4.7 |
| Apr 30 | 47650, 48000, 47650, 47988 | 0.02 | 21 | 0.14 |
| **Silver Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Nov 29 | 46101, 46750, 46083, 46687 | 113.7 | 17757 | 71.7 |
| Feb 28 | 46958, 47575, 46944, 47506 | 2.41 | 449 | 6.58 |
| **तेल एवं गैस** | | | | |
| **Gas** | | | | |
| **Natural Gas MCX(1 MB)** | | | | |
| Nov 25 | 192.2, 194, 191.1, 193.2 | 46441mb | 23649 | 20270mb |
| Dec 26 | 198.9, 201.4, 198.8, 200.6 | 2284mb | 1374 | 2883mb |
| Jan 28 | 197.4, 199.3, 196.9, 199 | 145mb | 109 | 593mb |
| **Oil** | | | | |
| **Crude Oil MCX(1 BL)** | | | | |
| Nov 19 | 3904, 3940, 3878, 3888 | 9927bl | 49822 | 2136bl |
| Dec 18 | 3934, 3957, 3900, 3910 | 165bl | 1174 | 74bl |
| Jan 17 | 3866, 3866, 3866, 3866 | 0bl | 1 | 1bl |
| **Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)** | | | | |
| Nov 19 | 3892, 3938, 3878, 3889 | 2230bl | 90474 | 550bl |
| Dec 18 | 3916, 3957, 3901, 3909 | 85bl | 4428 | 47bl |
| **सायं सत्र (बुधवार)** | | | | |
| **कृषि जिंस** | | | | |
| **Cotton** | | | | |
| **Cotton MCX(1 B)** | | | | |
| Oct 31 | 19490, 19570, 19490, 19560 | 247 | 49 | 455 |
| Nov 29 | 19450, 19480, 19320, 19440 | 2156 | 369 | 9090 |
| Dec 31 | 19480, 19480, 19330, 19410 | 438 | 76 | 4524 |
| **Kapas MCX(20 K)** | | | | |
| Apr 30 | 1085, 1088, 1082, 1086.5 | 248 | 60 | 388 |
| **Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)** | | | | |
| Apr 30 | 1085.5, 1087, 1080.5, 1086.5 | 499 | 342 | 3663 |
| **Oil and Oilseeds** | | | | |
| **Crude Palm Oil MCX(10 K)** | | | | |
| Oct 31 | 579.3, 582.3, 577.5, 580.1 | 16960 | 723 | 5910 |
| Nov 29 | 590.1, 596.9, 587.7, 592.4 | 29920 | 1674 | 57740 |
| Dec 31 | 593.6, 601, 591.6, 598 | 8730 | 583 | 12930 |
| Jan 31 | 590.5, 598.2, 590.5, 596.3 | 1230 | 62 | 4080 |
| **Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)** | | | | |
| Nov 20 | 770, 775.65, 768.15, 771.05 | 10770 | 815 | 29420 |
| Dec 20 | 773, 779.5, 771.8, 774.75 | 11810 | 749 | 17500 |
| Jan 20 | 775, 780.45, 774, 780.1 | 1040 | 59 | 980 |
| **धातु** | | | | |
| **Metal- non ferrous** | | | | |
| **Aluminium MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 130.3, 130.5, 130, 130.2 | 120 | 23 | 2340 |
| Nov 29 | 132.05, 132.8, 131.95, 132.35 | 10595 | 1662 | 13890 |
| Dec 31 | 134.85, 134.85, 134.3, 134.4 | 55 | 11 | 140 |
| **Aluminium Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 129.9, 130.55, 129.9, 130.2 | 72 | 23 | 992 |
| Nov 29 | 132.05, 132.8, 131.95, 132.35 | 3936 | 3038 | 4532 |
| Dec 31 | 134.1, 134.8, 134.1, 134.55 | 52 | 51 | 61 |
| **Copper MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 438, 439.2, 437.2, 438.25 | 377.5 | 136 | 1330 |
| Nov 29 | 443, 444.8, 442.6, 443.8 | 28050 | 9022 | 15070 |
| Dec 31 | 447.55, 449.25, 447.55, 448.45 | 312.5 | 118 | 787.5 |
| **Lead MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 165.55, 167.95, 162.5, 165.65 | 865 | 134 | 470 |
| Nov 29 | 159.5, 160.05, 157.5, 157.75 | 27955 | 4628 | 7875 |
| Dec 31 | 160.25, 160.25, 158, 158.6 | 75 | 15 | 175 |
| **Lead Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 160, 163.7, 158, 158.5 | 45 | 42 | 15 |
| Nov 29 | 159.6, 160, 157.55, 157.7 | 9870 | 7737 | 2070 |
| Dec 31 | 159, 159.95, 157.75, 158 | 222 | 191 | 101 |
| **Nickel MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 1216.9, 1244.4, 1210.7, 1237.2 | 44 | 141 | 48 |
| Nov 29 | 1200.7, 1212, 1199.2, 1207.1 | 6454 | 20286 | 2337.75 |
| Dec 31 | 1197.8, 1207.4, 1197.8, 1201.4 | 135 | 90 | 117 |
| **Zinc MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 189.75, 190, 187.2, 188.2 | 750 | 101 | 1410 |
| Nov 29 | 190.4, 191.1, 188.6, 189.05 | 46190 | 7306 | 11620 |
| Dec 31 | 192.55, 192.7, 190.5, 190.8 | 695 | 109 | 475 |
| **Zinc Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Oct 31 | 188.9, 190.25, 187.1, 188.75 | 197 | 90 | 170 |
| Nov 29 | 190.3, 191.05, 188.65, 189.05 | 14428 | 11361 | 2762 |
| Dec 31 | 192.45, 193.15, 190.55, 190.95 | 258 | 238 | 232 |
| Jan 31 | 195, 195, 193, 194 | 4 | 4 | 4 |
| **Metal- precious** | | | | |
| **Gold MCX(10 G)** | | | | |
| Dec 05 | 37920, 38129, 37894, 38088 | 10.37 | 8660 | 16.08 |
| Feb 05 | 38170, 38300, 38100, 38285 | 0.34 | 277 | 4.84 |
| **Gold Guinea MCX(8 G)** | | | | |
| Oct 31 | 31000, 31000, 30735, 30923 | 0 | 9 | 0 |
| Nov 29 | 30472, 30575, 30472, 30541 | 0 | 320 | 0 |
| Dec 31 | 30448, 30590, 30448, 30558 | 0 | 11 | 0 |
| **Gold Mini MCX(10 G)** | | | | |
| Nov 05 | 38194, 38384, 38078, 38369 | 0.64 | 3033 | 0.35 |
| Dec 05 | 37951, 38110, 37909, 38079 | 1.35 | 10920 | 0.64 |
| Jan 03 | 37975, 38151, 37970, 38135 | 0.08 | 661 | 0.1 |
| **Gold Petal MCX(1 Gm)** | | | | |
| Oct 31 | 4141, 4141, 3900, 3931 | 0 | 146 | 0 |
| Nov 29 | 3836, 3848, 3836, 3843 | 0.01 | 1552 | 0.01 |
| Dec 31 | 3836, 3852, 3834, 3849 | 0 | 112 | 0 |
| **Silver MCX(1 K)** | | | | |
| Dec 05 | 45850, 46384, 45850, 46119 | 709.83 | 18493 | 274.2 |
| Mar 05 | 46798, 47200, 46764, 46889 | 11.04 | 302 | 37.5 |
| **Silver Micro MCX(1 K)** | | | | |
| Nov 29 | 45900, 46379, 45860, 46146 | 55.49 | 39262 | 21.07 |
| Feb 28 | 46792, 47210, 46755, 46945 | 3.22 | 2388 | 4.4 |
| Apr 30 | 47500, 47650, 47400, 47497 | 0.02 | 17 | 0.12 |
| **Silver Mini MCX(1 K)** | | | | |
| Nov 29 | 45850, 46388, 45845, 46145 | 192.78 | 29525 | 54.16 |
| Feb 28 | 46735, 47200, 46730, 46958 | 3.26 | 608 | 6.08 |
| **तेल एवं गैस** | | | | |
| **Gas** | | | | |
| **Natural Gas MCX(1 MB)** | | | | |
| Nov 25 | 190, 193.8, 186.5, 191 | 172238mb | 86918 | 14931mb |
| Dec 26 | 198, 200.8, 194, 198.3 | 9280mb | 5713 | 2696mb |
| Jan 28 | 192.8, 198.9, 192.2, 196.5 | 444mb | 322 | 545mb |
| **Oil** | | | | |
| **Crude Oil MCX(1 BL)** | | | | |
| Nov 19 | 3945, 3957, 3870, 3880 | 24280bl | 123015 | 1470bl |
| Dec 18 | 3925, 3978, 3896, 3903 | 393bl | 2758 | 76bl |
| Jan 17 | 3977, 3977, 3916, 3951 | 1bl | 5 | 1bl |
| **Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)** | | | | |
| Nov 19 | 3955, 3957, 3870, 3879 | 5727bl | 215161 | 381bl |
| Dec 18 | 3950, 3978, 3896, 3905 | 208bl | 10746 | 44bl |

Name Exchange ( Units)

*g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.*

# केंद्र शासित राज्यों में बदला कश्मीर

## यह पहला मौका है जब किसी राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है

**एजेंसियां**

गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार देर रात जारी एक अधिसूचना के जरिये जम्मू कश्मीर गुरुवार को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तब्दील हो गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां लगे राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया हो। इस तरह, देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर नौ हो गई और राज्यों की संख्या घटकर 28 रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि नई व्यवस्था का लक्ष्य विश्वास की मजबूत कड़ी बनाना है। हालांकि कश्मीर घाटी में पिछले 88 दिनों की तरह गुरुवार को भी बंद जारी रहा।

यह कदम 5 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप उठाया गया है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्यों को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए जम्मू कश्मीर के लिए गिरीश चंद्र मुर्मू को और लद्दाख के लिए राधा कृष्ण माथुर को उपराज्यपाल बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने दोनों को उपराज्यपाल पद की शपथ दिलाई।

राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले के लागू होने के साथ जम्मू कश्मीर का संविधान और रणबीर दंड संहिता अस्तित्व में नहीं रह गए हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को देर रात जारी एक अधिसूचना में जम्मू कश्मीर राज्य की जगह जम्मू कश्मीर संघ राज्य प्रदेश शब्दावली का उल्लेख किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख बगैर विधानसभा वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात करते सलाहकार फारूख खान *फोटोः पीटीआई*

जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पांच साल की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद होगी जबकि लद्दाख का शासन उपराज्यपाल के जरिए सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के पास एक साझा उच्च न्यायालय होगा। लद्दाख अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के दायरे में आएगा। नए केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही वेतन तथा अन्य लाभ मिलने शुरू होंगे।

### नई शुरुआत

- देश में अब कुल 28 राज्य और नौ केंद्र शासित प्रदेश होंगे
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नई व्यवस्था का लक्ष्य विश्वास की मजबूत कड़ी बनाना
- कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलेंगे वेतन एवं दूसरे लाभ
- चीन पर भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा

### प्रधानमंत्री ने किया स्वागत

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और लोगों को राष्ट्रीय एकता संकल्प दिलाया। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के प्रावधानों से राज्य में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही फैला। उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नई व्यवस्था का मतलब जमीन पर लकीर खींचना नहीं, बल्कि विश्वास की मजबूत कड़ी बनाना है।'

### ईयू दौरा अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं : विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) सांसदों का कश्मीर दौरा इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए बिल्कुल नहीं था और इस तरह के शिष्टमंडल आधिकारिक माध्यमों से नहीं आया करते हैं। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अपनी पहली टिप्पणी में यह भी कहा कि महत्त्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस तरह का दौरा व्यापक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'हमें लगता है कि इस तरह की चीजें जनता के स्तर पर संपर्क का हिस्सा हैं।' उन्होंने कहा कि यह दौरा कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए बिल्कुल नहीं था। कुमार ने यह भी कहा कि ईयू सांसदों के विचारों ने कश्मीर में आतंकवाद के खतरे पर उनकी समझ को प्रदर्शित किया है।

# राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाएगी ट्विटर

**नेहा अलावधी**

**सोशल** मीडिया वेबसाइट ट्विटर के मुख्य कार्याधिकारी जैक डोर्सी ने गुरुवार को कहा कि माक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर वैश्विक स्तर पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाएगा और ऐसा करने वाली वह मुख्यधारा की पहली सोशल मीडिया कंपनी होगी। इसके साथ ही फेसबुक जैसे दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म से भी इसी तरह की पहल करने की मांग तेज हो गई।

लगातार कई ट्वीट करके डोर्सी ने इस कदम के पीछे छिपे कारणों को बताया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट विज्ञापन वाणिज्यिक विज्ञापनदाताओं के लिए 'अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली' एवं प्रभावी माध्यम है और इससे राजनीति के लिहाज से अहम जोखिम पैदा होते हैं क्योंकि यहां विज्ञापन का उपयोग लाखों लोगों के जीवन के प्रभावित करने वाले मतदान को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापनों का खर्च वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बनता जा रहा है, विशेषकर पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट सामने आने के बाद से यह चिंता बढ़ गई है। फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियों और राजनीति विज्ञापनों वाले दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक विज्ञापनों पर होने वाले खर्च से जुड़े आंकड़े जारी करके प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है।

डोर्सी ने लिखा, 'ये चुनौतियां सिर्फ राजनीतिक विज्ञापनों को नहीं बल्कि सभी तरह के इंटरनेट संचार को प्रभावित करेंगी। पैसों की मदद से बढ़ने वाले बोझ एवं जटिलता के बजाए मुख्य समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना सर्वश्रेष्ठ है।' डोर्सी बताते हैं कि कंपनी 15 नवंबर तक अंतिम पॉलिसी साझा कर देगी और 22 नवंबर से इस प्रतिबंध शुरू हो जाएगा। इस दौरान प्रसारित राजनीति विज्ञापनों को बदलाव के लिए निश्चित समय दिया जाएगा।

सूचना तकनीक पर संसदीय समिति के प्रमुख एवं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, 'ट्विटर द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों को समाप्त करना स्वागतयोगग्य कदम है। इन विज्ञापनों से अधिक वित्तीय सहायता पाने वाली राजनीति पार्टियों, विशेषकर सत्ताधारी दलों को लाभ मिलता था। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। अगर आप अपने राजनीतिक संदेश को ट्विटर पर प्रसारित करना चाहते हैं तो आपको फॉलोअर्स लाने होंगे, उसे खरीदना नहीं होगा।' अपने ट्वीट में डोर्सी ने लिखा, 'हमें राजनीतिक विज्ञापनों से जुड़े और अधिक नियमों की आवश्यकता है, हालांकि यह करना काफी जटिल होगा। एक प्रक्रिया के तहत विज्ञापनों में पारदर्शिता आती है लेकिन यह काफी नहीं है। इंटरनेट पूरी तरह से नई क्षमताएं उपलब्ध कराता है और नियामकों को एक समान मंच उपलब्ध कराने के लिए और अधिक सोच-विचार करने की आवश्यकता है।'

हालांकि इस कदम के बाद फेसबुक से भी इस तरह के कदम उठाने की मांग की जाने लगी। गुरुवार को तिमाही आंकड़े जारी करने के बाद फेसबुक ने कहा कि फिलहाल वह ट्विटर के रास्ते पर नहीं चलेगी और राजनीतिक विज्ञापनों के मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर देगी। फेसबुक के मुख्य कार्याधिकारी मार्क जकरबर्ग ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में नेताओं या खबरों पर रोक लगाना निजी कंपनियों के लिए ठीक है। हमने पहले भी इस बात पर विचार किया है कि हमें ऐसे विज्ञापन चलाने चाहिए या नहीं और हम आगे भी इस पर विचार करते रहेंगे। हालांकि अभी हमने इसे जारी रखने का निर्णय लिया है।'

उन्होंने गूगल, यूट्यूब, केबल नेटवर्क और टेलीविजन चैनलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे विज्ञापन चलाते हैं। जकरबर्ग ने कहा कि कंपनी ने इन विज्ञापनों को राजस्व के कारण जारी रखने का फैसला नहीं लिया है। यह फैसला इसलिए लिया है कि ये विज्ञापन उम्मीदवारों की अहम आवाज हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञापन अगले साल कंपनी के राजस्व में 0.50 प्रतिशत से भी कम योगदान देंगे।

### स्पाईवेयर : व्हॉट्सऐप से मांगा जवाब

**सूचना प्रौद्योगिकी** (आईटी) मंत्रालय ने इजरायली स्पाईवेयर (जासूसी सॉफ्टवेयर) के मुद्दे पर व्हॉट्सऐप से 4 नवंबर तक जवाब मांगा है। व्हॉट्सऐप ने कहा है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिये कुछ अज्ञात इकाइयां वैश्विक स्तर पर जासूसी कर रही हैं। भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने इस बारे में व्हॉट्सऐप को पत्र लिखकर अपना जवाब देने को कहा है। उधर, गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकों की निजता के उल्लंघन की खबरें देश की छवि धूमिल करने की कोशिश है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कोई भी बिचौलिया इकाई नागरिकों की निजता का उल्लंघन करते पाई गई तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। व्हॉट्सऐप ने कहा है कि वह एनएसओ समूह के खिलाफ मुकदमा करने जा रही है। यह इजरायल की निगरानी करने वाली कंपनी है। समझा जाता है कि इसी कंपनी ने वह प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसके जरिये अज्ञात इकाइयों ने जासूसी के लिए करीब 1,400 लोगों के फोन हैक किए हैं। *भाषा*

# आदित्य नहीं शिंदे को चुना गया शिवसेना नेता

**सुशील मिश्र**

**महाराष्ट्र** में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही खींचतान के बीच गुरुवार को शिवसेना के नवनिर्वाचित विधायकों ने एकनाथ शिंदे को विधानसभा में पार्टी का नेता चुना। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे आदित्य ठाकरे को यह पद दिया जाएगा। शिवसेना अभी तक अपनी मांग में अड़ी हुई है जबकि भाजपा शिवसेना को मनाने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया है जिसको लेकर जल्द ही दोनों दलों के बीच बात होगी। भाजपा कल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन चुकी है।

सरकार गठन में सहयोगी शिव सेना के अड़ियल रुख के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को तीन छोटी पार्टियों के 13 नव निर्वाचित सदस्यों में से 8 के साथ बैठक की। भाजपा को 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 26 विधायक कम पड़ रहे हैं। राज्य में नई विधानसभा के लिए 10 नवंबर तक का समय है। पिछली विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

शिवसेना विधायक दल की बैठक में पहली बार विधायक चुने गए आदित्य ठाकरे ने शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रताप सरनाइक ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके साथ ही सुनील प्रभु को शिवसेना का मुख्य सचेतक चुना गया। शिवसेना प्रमुख ने अपनी पार्टी के विधायकों को यह भी बताया कि भाजपा ने अभी तक सरकार गठन के लिए सत्ता बंटवारे के किसी फॉर्मूले की पेशकश नहीं की है। शिवसेना की बैठक के पहले भाजपा की तरफ से एक नए फॉर्मूले की बात सामने आयी जिसमें भाजपा सरकार गठन के लिए शिवसेना को 13 मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री पद देने का प्रस्ताव देगी। हालांकि भाजपा वित्त और गृहमंत्रालय अपने पास रखना चाह रही है।

**शिवसेना के नवनिर्वाचित विधायक एकनाथ शिंदे** *पीटीआई*